टिकाऊ शहर : एक पुनर्विचार

(सुगम, हरित और न्यायपूर्ण शहर)

सम्पादक : डेविड सायमन

MISTRA
URBAN
FUTURES

टिकाऊ शहर : एक पुनर्विचार

(सुगम, हरित और न्यायपूर्ण शहर)

सम्पादक : डेविड सायमन

MISTRA
URBAN
FUTURES

यह पॉलिसी प्रेस 2016 द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'टिकाऊ शहरों के पुनर्निर्माणः सुगम, हरित और न्यायपूर्ण' का एक अनूदित और संपादित सारांश है(आई एस बी एन 978–1–4473–3284–8, http://policypress-co-uk/rethinking-sustainable-cities), ePDF OAPEN के माध्यम से खुली पहुँच के द्वारा http://www-oapen-org पर उपलब्ध।

iihs®
INDIAN INSTITUTE FOR
HUMAN SETTLEMENTS

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंटस

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंटस (IIHS) एक राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान है जो कि भारतीय बसावटों के न्यायसंगतए टिकाऊ एवं सक्षमतापूर्ण रूपांतरण के लिए प्रतिवद्ध है। (IIHS) स्वतंत्र रूप से प्रबंधित एवं स्ववित्तपोषितए शोध एवं नवाचार के लिए श्रेष्ठतापूर्ण राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाहता है जो भारत के शहरी परिवर्तन की चुनौतियों और अवसरों पर केंद्रित हो।प्रस्तावित IIHS विश्वविद्यालय एक श्रेष्ठ संस्थान होगा जो गुणवत्तापूर्ण कैम्पस.आधारित शिक्षा प्रदान करेगा।साथ ही साथ यह कार्यरत पेशेवरों के लिए शोधएप्रशिक्षण एवं आजीवन अधिगम के लिए भी काम करेगा।यह दूरस्थ एवम मिश्रित शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ व्यवहार एवम परामर्श की पूरी श्रृंखला पर काम करेगा।विश्वविद्यालय का बलपूर्ण अंतर्विषयक झुकाव होगा जो दक्षिण एशियाई सन्दर्भ में सिद्धांत एवं व्यवहार को करीब लाएगा।इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर के ज्ञान के साथ रिश्ता बनाएगा एवम उससे समृद्ध होगा।

अधिक जानकारी के लिए देखें.
http://iihs.co.in

अनुवाद उपक्रम

IIHS अनुवाद उपक्रम 2017 में बनाया गया जिसका उद्देश्य भारत मे सीखने.सिखाने के स्पेस को लगातार द्विभाषी या बहुभाषी होते जाने से उत्पन्नअधिगमए ज्ञान.निर्माण एवम ज्ञान.विनिमय के सामने आने वाली चुनौतियों को सम्बोधित करना है।यह उपक्रम प्रकाशकोंए लेखकों एवं अनुवादकों के साथ मिलकर भारत एवं पूरी दुनिया में सुदृढ़ अनुवाद.तंत्र बनाने के लिए समझ हासिल करने एवं सहयोग करने के लिए काम करता है।इसके अतिरिक्त यह शहरी शोध एवं अभ्यास की परियोजना से रिश्ता बनाएगा तथा व्यवहारकर्मियो के समुदाय का निर्माण करेगा जो प्रयोग एवम एकेडेमिक्स की सामग्रियों का अनुवाद करने में सक्रिय भूमिका निभाएगा।

विषय – सूची

परिचय	05
सुगम शहर	08
हरित शहर	22
न्यायपूर्ण शहर	30
निष्कर्ष, परिणाम एवं व्यावहारिक दिशा निर्देश	39

लेखकों का परिचय

डेविड सायमन स्वीडन मे शाल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलोजी के मिस्त्रा अरबन फ्यूचर्स के 2014 से डायरेक्टर हैं। 1999 से वे लन्दन के रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट जिओग्रफी के प्रोफेसर हैं। उनकी शोध संबंधी रुचियाँ शहरों, टिकाऊपन और जलवायु परिवर्तन के विषय में हैं। डेविड सायमन की बड़ी संख्या में लेख, पुस्तक अध्याय और पुस्तकें व्यापक रूप से प्रकाशित हुई हैं।

हेनेरिटा पामर एक आर्किटेक और शाल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलोजी के आर्किटेक्चर और सिविल विभाग की आर्टिस्टिक प्रोफेसर हैं। वे मिस्त्रा अरबन फ्यूचर्स में डेप्युटी साइंटिफिक डायरेक्टर भी हैं। हेनेरिटा पामर स्टाकहोम के रॉयल इंस्टिट्यूट ऑफ आर्ट्स में सक्रिय रही हैं, जहाँ उन्होंने अंतरविषयक कार्यक्रम संसाधनों को विकसित किया। उनके शोध परिवर्तन की प्रक्रियाओं और उनकी द्रश्य अभिव्यक्तियों के विषय में है।

सू पारनेल अरबन जिओग्रफी की प्रोफेसर और दक्षिण अफ्रिका के यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में अफ्रिकन सेंटर ऑफ सिटीज के जनकों में एक हैं। हाल ही में वे क्लाइमेट एट अ सिटी स्केल, द रूट्लेज हैंडबुक ऑन सिटीज ऑफ ग्लोबल साउथ और अफ्रिकाज अरबन रिवोल्यूशन किताबों की सह–सम्पादक रही हैं।

जेम्स वाटर्स अरूप इंटरनैशनल डेवलपमेंट में शोधकर्ता और परामर्शी हैं। वे अरबन रेजिलिएंस रिसर्च नेटवर्क के जनकों में एक हैं और उन्होंने शहरी प्रतिरोधक क्षमता, प्रवास और शहरों के निर्धन निवासियों पर कई लेख लिखे हैं।

1. परिचय

डेविड साइमन

हाल के वर्षों में टिकाऊ शहरीकरण शोधकार्य एवं राजनीतिक कार्यसूचियों में बहस का एक अहम मुद्दा बन गया है। इसके कई कारण हैं और जो कारण अहम बनते हैं उसके पीछे देशों तथा क्षेत्रों के बीच भिन्नता है। फिर भी, चीन, भारत तथा निम्न व मध्य आय तथा ऐतिहासिक तौर पर शहरीकरण के निचले स्तर वाले देशों में तेज शहरीकरण के परिणामों को लेकर जागरूकता सबसे महत्त्वपूर्ण है। प्रायः शहरीकरण में ये देश उन अदीर्घकालिक एवं प्रचुर साधनों पर निर्भर शहरीकरणं का अनुसरण करते हैं, जिनके जरिये उच्च आय वाले देश विकसित हुए थे। बढ़ी हुई वैश्विक आवाजाही, आर्किटेक्टों, शहरी नियोजन– सलाहकारों एवं निर्माण कंपनियों, मीडिया, के वैश्वीकरण नई सूचनाओं और संचार तकनीकों की प्रसार–शक्ति तथा इनके तीव्र वैश्विक आवागमन के चलते यह चलन और बढ रहा है।

इसी तरह, दुनिया के कई शहरों तथा क्षेत्रों ने जलवायु तथा पर्यावरणीय बदलावों के रूप में संभावित चुनौतियों तथा उनसे निबटने को लेकर तेज कार्रवाई के महत्त्व को समझना शुरू कर दिया है। गरीब शहरों तथा क्षेत्रों के लिए भी यही सच्चाई है। इससे कुछ वर्षों पूर्व तक की स्थिति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जब इस तरह की दलीलें अनसुनी रह जाती थीं, क्योंकि संसाधनों की तात्कालिक जरूरतों की तुलना में ये समस्याएं सुदूर भविष्य में घटने वाली प्रतीत होती थीं। लगभग हर जगह, मौसम में उतार–चढ़ाव और इसके अप्रत्याशित उदाहरण, खासकर चरम आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और उनकी भयावहता तथा जनजीवन की व्यापक क्षति एवं आर्थिक व पर्यावरणीय हानि की वास्तविकताएं राजनीतिज्ञों, अधिकारियों तथा आम नागरिकों की समझ को समान रूप से बदल रही हैं।

शहरी मुद्दे, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा बन चुके हैं, यह उनकी बढ़ती अहमियत की एक प्रमुख निशानी है। शहरों को समावेशी, सुरक्षित, लचीले तथा टिकाऊ बनाने का खास शहरी लक्ष्य (नंम्बर 11) अब संयुक्त राष्ट्र की 2015 की आमसभा द्वारा अपनाए गये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स(सतत विकास लक्ष्यों) (क्ळे) के ढांचे में सम्मिलित है। ये एसडीजीज़ 2016 से मिलेनियम सस्टेनेबल गोल्स (सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों) (डक्ळे) की जगह प्रतिस्थापित हैं। एमडीजीज़ के विपरीत, एसडीजीज़ का प्रतिपादन एक जटिल व मुक्तलिफ विमर्शात्मक प्रक्रिया के जरिये किये गये थे, जिसमें राष्ट्रीय तथा उप राष्ट्रीय सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, गैरसरकारी संगठन (एनजीओज़),निजी क्षेत्र तथा हर देश की सामुदायिक ऐजेंसियां सम्मिलित रही थीं। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है कि ये लक्ष्य प्रतिव्यक्ति आय अथवा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स(मानव विकास सूचकांक) (भ्र्क्)पर बिना किसी विभेद पर आधारित सभी देशों पर लागू हैं। यह स्थिरता की चुनौतियों के सम्मुख मानव जाति के साझी नियति के प्रश्न को सामने लाती है। ये चुनौतियां बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हेतु संसाधनों तथा जीवन की स्वीकार्य गुणवत्ता तक नाकाफी पहुंच अथवा अत्यधिक उपभोग और उससे संबंधित सवास्थ्य, संसाधनों की कमी, तथा पर्यावणीय समस्याओं से संबंधित हैं।

दुनिया भर में, शहरी क्षेत्रों का जनसांख्यिकीय, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक –सांस्कृतिक महत्त्व लगातार बढ़ रहा है। शहरों तथा अन्य उपराष्ट्रीय तत्वों का जिक्र पहली बार 2015 की शुरुआत में पेरिस में हुए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (पर्यावरणीय बदलाव पर संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सम्मेलन) (न्छथ्ब्ब) में हुआ था। यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने को लेकर शहरी क्षेत्रों की भूमिका को विशेष मान्यता देता है। उसी समय, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने दुनिया भर के विभिन्न हितधारक समूहों के साथ नई शहरी कार्यसूची को सक्रिय रूप से तैयार किया। आधिकारिक तौर पर नई

षहरी कार्यसूची की शुरुआत अक्टूबर 2016 में क्विटो, इक्वाडोर में संपन्न हुए तृतीय आवास वैश्विक सम्मेलन में की गयी जिसे आने वाले बीस वर्षों तक अधिक टिकाऊ शहरीकरण तथा टिकाउ शहरी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों को आकार देना है। शहरी टिकाउपन का महत्व अब व्यापक मान्यता प्राप्त कर रहा है, जो इस मकसद की दिशा में प्रगति के लिए पहली पूर्वदशा की तरह है। फिर भी, इसमें एक विरोधाभास है। पहली नजर में यह लग सकता है कि उच्च आय वाले देशों के संसाधनयुक्त, सुव्यवस्थित शहरों नगरों–महानगरों को टिकाऊ बनाना ज्यादा सरल है लेकिन वहाँ संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर, बहुत ज्यादा उपभोग करने वाली आर्थिक प्रक्रिया तथा जीवन शैली है साथ ही शक्ति–संबंधों एवं निहित स्वार्थ की बाधा भी है जिन्हें पार करने के लिए बहुत अधिक प्रयास, एवं राजनैतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है।

इसके उलट, कई लोगों के लिए गरीब देशों के तेजी से वृद्धि हासिल कर रहे शहर जिसमें व्यापक गरीबी, संसाधनों और सेवा का अभाव तथा भारी यातायात में बढ़ोतरी– निर्णायक चुनौती अथवा 'दुर्दम्य' शहरी समस्या'का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी, यद्यपि निहित स्वार्थ वहां भी हैं और बदलाव का जबरदस्त विरोध हो सकता है, पूर्व प्रशासक बाबाटुंडे फाशोला के शासन में नाइजेरिया के सबसे बड़े शहर लागोस का उदाहरण दर्शाता है कि कैसे निजी भ्रष्टाचार से अछूता, समस्या के प्रति प्रतिबद्ध कोई ऊर्जावान सही संबंद्धताओं के साथ अपेक्षाकृत कम समय में भी उल्लेखनीय नतीजे ला सकता है, यहां तक कि, सबसे गंभीर समस्याओं वाले किसी महानगर में भी।

निःसंदेह, यद्यपि टिकाऊ हों या कि न हों लेकिन शहर ईंटों, कंक्रीट, लोहा, शीशा, रोड़ी, लोहे, लकड़ी और कार्डबोर्ड आदि के पृथक द्वीपों जैसे नहीं होते। वस्तुतः ये व्यापक प्राकृतिक तथा राजनीतिक–प्रशासनिक क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय व पराराष्ट्रीय अस्तित्त्वमान तत्वों के अभिन्न अंग होते हैं, जिनपर ये संसाधनों, कचड़ा निकासी, मनुष्यों के बीच परस्पर क्रियाओं तथा लोगों की आवाजाही, उपभोग की वस्तुओं एवं वित्त के लिए आश्रित होते हैं। शहरी क्षेत्र टिकाऊपन की तरफ परिवर्तन में आगे या पीछे रह सकते हैं, लेकिन अंततः टिकाऊ कस्बे और शहर अधिक अथवा कम टिकाऊ समाजों के अंग सरीखे होते हैं। यह विभिन्न महाद्वीपों पर विद्यमान अनेक प्राचीन शहरी समाजों से संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर भी व्यक्त होते हैं, चूंकि, परस्पर क्रिया–प्रतिक्रिया कर रही व्यवस्थाओं का विस्तार प्रायः अनेक प्रशासनिक क्षेत्रों तक होता है, यह जटिलता 'सीमा–स्पर्शी समस्या ;इवनदकतल चतवइसमउेद्धश पैदा करती है तथा पहले से ही जटिल विकास, आर्थिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, सामाजिक एवं तकनीकी चुनौतियों को और जटिल बनाती है। टिकाऊपन कई तरह से अपने आप में एक जटिल व विवादग्रस्त खयाल है। इसमें विविध घटकों का समावेश होता है– कुछ आसानी से मापने योग्य तो दूसरे कहीं अधिक गुणात्मक होते हैं।

इसके अतिरिक्त, विकास की तरह टिकाऊपन में तिहरी विशिष्टताएं होती हैं– एक आदर्श आकांक्षा, समुदाय के लिए एक आदर्श अवस्था की अवस्थिति तथा इस अवस्था को प्राप्त करने के साधन। अनेक विमर्शों तथा अमलीकरणों में इसका सिद्धांतीकरण, औचित्यीकरण, उपयोग तथा दुरुपयोग किया गया है। इस हद तक कि कुछ आलोचकों का दावा है कि विकास की तरह ही यह अपनी उपयोगिता खो चुकी है। इनमें से कुछ जटिलताओं की परख शहरी संदर्भ में अध्याय तीन में की गयी है। खासकर, 'हल्के जोर वाले' ॅ;मांद्ध एवं 'अधिक जोर वाले' ॅ;जतवदहद्ध सातत्त्य विमर्शों के बीच, नीतियों एवं कार्यों के बीच के विभेदों की तथा आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय आयामों को एकीकृत करने की जरूरत की।

टिकाऊ शहर : एक पुनर्विचार

इस पुस्तक का मकसद आधिकारिक हस्तक्षेपों के प्रयोग से टिकाऊ शहरीकरण के लिए तैयार कार्यसूची को समझने में सहयोग करना है। यह साफ तौर पर सभी टिकाऊ नगरों एवं महानगरों के तीन मुख्य आयामों के महत्त्व, प्रासंगिकता का मूल्यांकन तथा व्याख्या के साथ उसे संदर्भित करती है। अर्थात इन्हें सुगम, हरित व न्यायपूर्ण होना चाहिए। ये तीनों आयाम 'मिस्ट्रा अरबन फ्यूचर्स' (डन्थ्) के कार्य को सामने लाते हैं। डन्थ् टिकाऊ शहरीकरण पर काम करने वाला गोटेबोर्ग्र, (स्वीडेन) स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शोध केन्द्र है, जो स्कैन (दक्षिणी स्वीडेन),ग्रेटर मैनचेस्टर(यूके), केप टाउन(दक्षिण अफ्रीका) तथा किसुमु(केन्या) स्थित पारआनुशासनिक शोध मंचों के जरिए संचालित होता है। ये मंच विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों, शोधार्थियों के समूहों तथा पैरास्टेटल्स, स्थानीय तथा क्षेत्रीय प्राधिकरणों व आधिकारिक एजेंसियों को एक साथ लाते हैं ताकि समस्याओं की पहचानकर उनके समाधान पाने तथा उन्हें लागू करने की दिशा में संयुक्त शोध प्रारंभ किये जाएँ। अधिकतर महाद्वीपीय क्षेत्रों में एक शोधमूलक उपस्थिति स्थापित करने के क्रम में 2016–17 में एशिया एवं/अथवा लैटिन अमेरिका में एक नई साझेदारी की योजना बनी है, जो उचित कार्य के दिशानिर्देशों तथा सिद्धांतों के तुलनात्मक अध्ययन का दायित्व उठाने की मिस्ट्रा अरबन फ्यूचर्स की क्षमता को बढ़ाएगी और इसके जरिए सभी स्तरों पर शहरी टिकाऊपन कार्यसूचियों को प्रभावित करेगी।

अपने दूसरे चरण के शोध कार्यक्रम में 'मिस्ट्रा अरबन फ्यूचर्स' ने सुगमतापूर्ण, हरित एवं न्यायपूर्ण शहरों से संबंधित मौजूदा साहित्य की विस्तृत समीक्षा का दायित्व लिया है। यह दुनिया भर में जारी शहरी टिकाऊपन संबंधी बहसों को प्रभावित करने को भी संभव बनाता है। इन बहसों में कई अक्टूबर 2016 में हुए तृतीय आवास सम्मेलन ;भ्इपजंज प्प्प्द्ध नउउपजद्ध की तैयारी मूलकप्रकिया में सामने आये हैं तथा अगले दो दशकों के लिए नई कार्यसूची के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर तथा बाहर समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। इन बहसों कें आसंग में यह पुस्तक स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं तथा व्यवहारकर्मियों के समक्ष आधार तथा संदर्भ के रूप में सामने आती है। इन लोगों के सामने दोहरी चुनौती है। जहाँ एक तरफ इन पर अनेक नये शहरी क्षेत्रों के निर्माण (जिन्हें कभी कभार 'भविष्य का शहर' कहा जाता है) तथा फैल़ रहे शहरों में नये शहरी हिस्सों की जिम्मेदारी है, वहीं पुराने शहरी क्षेत्रों का फिर से डिजाइन करना है। और यह डिजाइन दुनिया भर में अलग–अलग संदर्भों में उभर रहे उत्तम शहरी टिकाऊपन पद्धति के आधार पर करना है। ये सिद्धांत टिकाऊ शहरों एवं शहरी योजनाओं पर विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रमों तथा पेशेवर प्रशिक्षण इकाइयों में समान रूप से तेजी से केन्द्रीय स्थान पा रहे हैं।

2. सुगम शहर

जेम्स वाटर्स

परिचय

यह अध्याय शहरी नीति और नियोजन में पहुँच–सुगमता (अभिगम्यता) की अवधारणा के कुछेक लाभों और प्रतिकूलताओं तथा इसके विभिन्न आयामों का मूल्यांकन कैसे हो सकता है, पर विचार करता है।

मुख्यधारा की शहरी नीति में, सामान्यतः घनत्व को शहरी नियोजन के लिए एक सकारात्मक लक्ष्य माना जाता है। विश्व बैंक की दलील है कि 'घनत्व ही दरअसल फर्क पैदा करता है', तथा इसने कई वर्षों तक इसे केन्द्रीय सिद्धांत के रूप में अपनाए रहा। इस दौरान यूरोपीय नीति के अंतर्गत टिकाऊ विकास में सफलता के लिए सघनीकरण को बढ़ावा दिया गया। फिर भी, शहरी घनत्व के तुलनात्मक फायदों के इर्द–गिर्द दलीलें बहुत स्पष्ट नहीं हैं। और बिलकुल हाल की चर्चाओं ने भी पहुँच की सुगमता के महत्त्व पर बल दिया है। सघनीकरण के पक्ष में अधिकाश दलीलें संघनन के माध्यम से उत्पन्न आर्थिक मूल्य,शहरों की आर्थिक क्षमता, अधिक संसाधन क्षमता तथा परिवहन के इस्तेमाल तथा सेवाओं तक बेहतर पहुंच के इर्द– गिर्द तैयार की गयी हैं। तथापि घनत्व के साथ अनेक व्यापक मुद्दे जुड़े हैं, जिनमें आवास की आसान उपलब्धता, गोपनीयता, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य, अपराध, जैव–विविधता तथा ऊर्जा का इस्तेमाल शामिल हैं।

कुल मिलाकर, सघनता के तीन मुख्य फायदों की पहचान की गयी है–शहरी भूमि का अधिक सफल तथा गहन इस्तेमाल, बुनियादी ढांचा तथा कार द्वारा यात्रा में कमी, अधिक उत्पादक अर्थव्यवस्थाएं और अधिक जीवंत व समावेशी समुदाय।

शहरी क्षमता एवं पर्यावरणीय असर

सघनता के चिह्नित फायदों में से एक– छोटी यात्राओं के कारण निम्नतम जीवाश्म ईंधन का उत्सर्जन तथा विकास के निम्नतर स्तर के कार्बन फुटप्रिंट का होना है। निकटता सार्वजनिक परिवहन को अधिक व्यावहारिक बनाती है। तथा साइकिल चलाना अथवा पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने के साथ ही निजी वाहन के प्रयोग को तथा इसके द्वारा पैदा प्रदूषण को भी घटाता है। इसके अतिरिक्त 'ट्रांजिट–ओरिएंटेड डेवलपमेंट' परिवहनोन्मुख विकास(ज्व्व्) के द्वारा प्रेरित विकास सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के गिर्द भौतिक रूप से अनुकूल होता है तथा यात्रा की अवधि और दूरी को घटाता है। पैदल चलने की तरफ ध्यान देने वाला विकास को सार्वजनिक परिवहन जंक्शनों के साथ जोड़ने से, लोगों को पड़ोस से बाहर की यात्राएं के लिए सार्वजनिक परिवहन तथा अपने पड़ोस में यात्रा के लिए पैदल चलने तथा साइकिल से चलने की संभावना बढ़ती है।

'स्मार्ट शहरों' में, डिजिटल तकनीकों अथवा सूचना एवं संचार तकनीकी(प्ब्ज)का उपयोग शहरी सेवाओं को बढ़ाने, लागत तथा संसाधन खपत को घटाने तथा नागरिकों से अधिक प्रभावशाली तरीके से जुड़ने के लिए किया जा रहा है(देखें अध्याय 3)। उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में विभिन्न प्रयोजनों को मिश्रित कर तथा अधिक सक्षम बुनियादी ढांचे के द्वारा जमीन के उपयोग के स्तर में वृद्धि की जा सकती है। जहां तक सड़कों, पानी, सीवरों तथा तूफानी जल के नालों के विस्तार किये जाने की जरूरत नहीं पड़ती यह हरित क्षेत्र तथा कृषि भूमि पर पड़ने वाले विकास के दबाव को कम करता है तथा मौजूदा हरित क्षेत्र पर भी कम दबाव पड़ता है। नतीजतन शहरी जीवन की गुणवत्ता सुधर सकती है।

दूसरी ओर व्यापक घनत्व हमेशा निजी कार यात्राओं में कमी नहीं लाता और वस्तुतः यह यातायात जाम तथा पार्किंग की समस्या पैदा कर सकता है और बड़ी संख्या में सड़क हादसों का कारण भी बनता है। उच्च घनत्व वाली इमारतों का निर्माण पदयात्रियों के लिए दिक्कत का कारण भी बन सकता है, खासकर, सार्वजनिक परिवहन के इर्द–गिर्द। उच्च–घनत्व वाली इमारतों, खासकर गगनचुंबी इमारतों के निर्माण में ऊर्जा का भी अधिक उपयोग होगा। भूमि उपयोग से संबद्ध असुविधाओं में खुली सार्वजनिक जगह की कमी तथा शहरी क्षेत्रों की बारिश और वायु प्रदूषण से निबटने की घट गई क्षमता शामिल है।

अफ्रीका के उप–सहाराई इलाकों इत्यादि में, तेजी से और व्यापक स्तर पर प्राकृतिक क्षेत्रों का रूपांतरण शहरी भूमि में हो रहा है, प्रायः कम घनत्व वाले विस्तार से तथा उच्च घनत्व से युक्त तेज विकास के रूप में भी। इसलिए, घनत्व के साथ संबंध स्पष्ट नहीं है। दूसरी ओर, यूरोपियन शहरी विकास से उत्पन्न मजबूत साक्ष्य हैं। उदाहरण के के लिए, ब्रिटेन में उच्चतर शहरी घनत्वों वाले क्षेत्रों में घटते हरितीमा आच्छादित क्षेत्रों से तथा पानी व ताप नियमन व्यवस्था एवं कार्बन –पृथकीकरण जैसी पारिस्थितिकी क्रियाएं बांधित होती । भविष्य में पहले से घने शहरी क्षेत्रों में हरियाली युक्त जगहें बनाए रखने वाली उ़च्च घनत्व की नई इमारतों के लिए स्थान पाना और उनका निर्माण ज्यादा मुश्किल हो जायेगा।

संघटन एवं आर्थिक फायदे

साक्ष्य संकेत करते हैं कि विशाल फैले शहरों के बुनियादी ढांचे, रखरखाव तथा परिचालन लागत के वित्तपोषण की तुलना में उच्च घनत्व वाला विकास उल्लेखनीय रूप से सस्ता है। हालांकि, उच्च घनत्व के नकारात्मक आर्थिक नतीजों के साक्ष्य भी हैं। उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में उच्च घनत्व वाली इमारतों तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण में अकसर अधिक लागत आती है। ज्यादा महंगी भूमि के चलते, निवासीं को अवकाश के स्थानों से वंचित हो सकते हैं तथा रहन –सहन, वस्तुओं एवं सेवाओं की सापेक्षिक कीमतें अधिक हो सकती हैं।

आर्थिक फायदों व नुकसानों के अधिकतर प्रमाण अमेरिका, आस्ट्रेलिया अथवा ब्रिटेन जैसे देशों से आते हैं और हर अलग–अलग संदर्भ में इसके भिन्न होने की संभावना होती है। इसलिए, लाभों और हानियों की प्रासंगिक समझ अनिवार्य होती है।

संघटन एवं आर्थिक फायदे

उच्च घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों के सामाजिक प्रभाव विभिन्न तरह के हैं तथा सामाजिक साम्यता के लिए सापेक्ष फायदे विवादित हैं। सामाजिक व मनोवैज्ञानिक लाभों में शामिल हैं–

- घने क्षेत्रों में आवास हासिल कर पाने में वृद्धि
- किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बड़ी संख्या इसे सुरक्षित, अधिक विवधतापूर्ण पहुँच में सुगम तथा बसने योग्य बना सकते हैं
- परस्पर धनात्मक सामाजिक अंतर्क्रिया की संभावना है
- साथियों के लिए व्यापक विकल्प, खासकर बच्चों के लिए

सामाजिक व मनोवैज्ञानिक नुकसान भी हो सकते हैं:

- स्थान की कमी वाला रिहाइसी परिवेश तंगी, शोरपूर्ण, और गोपनीयता के अभाव का कारण बन सकता है
- इमारतों में निकटता का मतलब अभिभावकों का बच्चों पर कम निगरानी संभव
- समुदाय का भाव कम हाने से तनाव, चिंता और असामाजिकता संभव

यह घ्यान देना जरूरी है कि इन प्रभावों को घनत्व के आंकड़ों के साथ समरूपता दिखा पाना कठिन है क्योंकि जो क्षेत्र एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में बसने योग्य है, वही दूसरे में नहीं। ऐसे में जो अहम प्रतीत होता है वह घनत्व नहीं बल्कि विकास का ढंग है। सामाजिक बराबरी के नजरिए से भी प्रमाण समान रूप से मिश्रित है। सघन शहरी आवास के फायदों में प्रमुख सेवाओं की एक रेंज, खुली जगह, चहलकदमी वाली दूरी के भीतर रोजगार के अवसरों के चलते मिलते हैं। घनत्व मुख्य सेवाओं को सुगम बना सकता है, खासकर बेरोजगारों, वृद्धजनों अथवा युवा परिवारों के समूहों के लिए तथा श्रम बाजार में कमजोर वर्गों को रोजगार तक की पहुंच में सुधार लाता है। हालांकि, उच्च शहरी सघनताएं कई बार सामाजिक असमानता तथा अलगाव को भी बढ़ाता है तथा यह हो सकता है कि वस्तुओं, सेवाओं तथा बसाव की सापेक्षिक कीमतें अधिक हों।

यह पॉलिसी प्रेस 2016 द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'टिकाऊ शहरों के पुनर्निर्माणः सुगम, हरित और न्यायपूर्ण' का एक अनूदित और संपादित सारांश है(आई एस बी एन 978–1–4473–3284–8, http://policypress-co-uk/rethinking-sustainable-cities), ePDF OAPEN के माध्यम से खुली पहुँच के द्वारा http://www-oapen-org पर उपलब्ध।

न्यूयॉर्क सिटी (अमेरिका) के मैनहटन बरो, टोक्यो (जापान), सिंगापुर और हांगकांग में विश्व के कुछ उच्चतम आवासीय घनत्व हैं (चित्र)। (चित्र/डेविड सायमन)

समझौते व राजनीतिक तत्त्व

शहरी घनत्व की विशिष्टताओं से जुड़े लाभों एवं नुकसानों का संयोजन 'शहर के श्रेष्ठ आकार'की खोज में प्रकट हुआ था। हालांकि, 1970 के दशक की शुरुआत में ऐसी चर्चाओं को गैर–भरोसमंद मानकर खारिज कर दिया गया और 'श्रेष्ठ आकार' के साक्ष्य अस्पष्ट दृष्टिगोचर हुए, इसके अतिरिक्त एक क्षेत्र में लाभ का दूसरे क्षेत्र के लाभ के साथ समझौता संभव था जबकि, सघनीकरण समर्थक दलीलों के पीछे का राजनीतिक एजेंडा प्रस्तुत साक्ष्यों में से कुछ के चयन को प्रेरित कर सकता है।

तालमेल के दो मुख्य क्षेत्र हैं: सामाजिक आयामों के भीतर और आर्थिक दक्षता प्राप्ति एवं पर्यावरणीय स्थिरता के बीच तालमेल। आर्थिक दक्षता के संदर्भ में जो तालमेल हो सकते हैं, वे हैं –बुनियादी ढांचा प्रबंध की दक्षता तथा कार उपयोग एवं घटी सामर्थ्यशीलता व हरियाली के बीच। सामाजिक तौर पर, सामाजिक टिकाऊपन के दो मुख्य आयाम–सामाजिक साम्य तथा टिकाऊ समुदाय। घनत्व बढ़ने के साथ अकसर ये विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। जबकि, कुछ सामाजिक पहलू सघनता के साथ सुधरते हैं(उदाहरण के लिए, सेवाओं की सुलभता तथा गैर माटर विहीन परिवहन), अन्य और बुरे हो जाते हैं(उदाहरण स्वरूप, हरित स्थान की व्यवस्था, असुरक्षा की भावना तथा सामाजिक संपर्क)। इसी तरह, सामाजिक साम्यता के पहलुओं– जैसे सामाजिक अलगाव अदि में सुधार संभव है जबकि, सामर्थ्ययोग्य रिहाइस की उपलब्ध्ता सरीखे पहलुओ में गिरावट आती है।

सघनीकरण की बहस जब शहरी क्षमता और नई खोजों पर केन्द्रित होती है, तो वहां एक जोखिम है कि वे सिर्फ पारिस्थितिक आधुनिकीकरण को तेज करने पर चर्चा करते हैं और टिकाऊ शहरों पर बहस की संकीर्ण कर देते हैं, और यह संभवतः सामाजिक मुद्दों तथा व्यापक पर्यावरणीय स्थिरता की कीमत पर।

राजनीतिक संदर्भ सघनता को प्रभावित कर सकता है लेकिन किनके हित में काम हो रहा है पर भी विचार होना चाहिए। सघनीकरण– समर्थक दलीलें प्रायः शहरी डिजाइन आधारित विमर्श को लागू करने वाले पेशेवरों द्वारा समर्थित होती हैं तथा तकनीकीवादी नियोजन आधारित तरीको में राजनीतिक भूमिका सीमित हो सकती है।

शहर के प्रतिमान एवं सिद्धांतों का प्रयोग

शहरी विकास के तीनों वर्तमान प्रतिमान घनत्व के तर्कों पर बनते हैं:

- सघन शहर,
- बहुकेन्द्रित शहर
- तथा स्मार्ट शहर।

ये फैलाव को सुधार कर कार –निर्भर शहरी विकास के बरम्स, सार्वजनिक परिवहनोन्मुख शहरों की तरफ झुके होते हैं।

सघन शहर, घने शहरी रूपों तथा पैटर्नों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। वे शहरी घनत्व के इर्द–गिर्द अनेक उपर्युक्त सकारात्मक तर्कों के समर्थन पर निर्भर रहे हैं यथा संसाधन क्षमता तथा नई तकनीकी के इस्तेमाल, ग्रामीण भूमि पर कम विकासमूलक दबाव, कम से कम ऊर्जा उपयोग, बुनियादी ढांचे में कम लागत, रहन–सहन की उच्चतर गुणवत्ता तथा उच्चतर सामाजिक संबद्धता के साथ भी जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त वर्णित उच्च घनत्व के नुकसान हैं, जिनमें भीड़, किफायती आवासों का अभाव, अपराध में वृद्धि, जाम, हरित स्थान की कमी तथा प्रदूषण भी शामिल हैं।

बहुकेन्द्रिक शहर को गलियारे के साथ तारा–आधारित अथवा उपग्रह आकारिकी के आधार पर डिजाइन किया जाता है। ये शहरी विकास के मुद्दों को संबोधित करता है यथा शहरी जैवविविधता की गुंजाइश बनाने, जीवंत तथा विविधतापूर्ण पड़ोसों के निर्माण, आसानी से पहुंच वाली जगहों के निकट विकास को केन्द्रित कर यात्रा अवधि को घटाने आदि पर। बहुकेन्द्रिक शहरों का मकसद सामाजिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों के केन्द्रों पर ध्यान देते हुए विस्तृत फैलाव वाले शहरों तथा सघन शहरों–दोनों के फायदे मुहैया कराना होता है। ये सामाजिक एवं व्यावसायिक क्रियाओं के केन्द्रों पर फोकस करते हैं जो विभन्न पड़ोंसों के गिर्द बने समुदायों से बने होते हैं। इन पड़ोसी इलाकों में निजी गतिविधियों तथा सार्वजनिक सेवाओं की विविधता शामिल होती है, जो सहज निकटता के दायरे में होती है इस तरह कार का उपयोग कम तथा सार्वजनिक परिवहन, पैदल चलने साइकिल चलाने का उपयोग किया जाता है।

तीसरा और सबसे हालिया तथा नामित तथाकथित स्मार्ट शहरों का है, जहां स्मार्ट विकास में परिवहन, भूमि अनुमान, संरक्षण तथा आर्थिक विकास के समन्वय के माध्यम से अधिक दक्षताओं की प्राप्ति होती है। तेज विकास का तर्क नवाचार को बढ़ावा देने तथा निजी संपत्ति बाजार को नयी दिशा देने के लिए दिया जाता है, ज्ञान संचार के साथ ठोस बुनियादी ढांचे तथा सामाजिक ढांचे(मानव व सामाजिक पूंजी) के एकीकरण के जरिए संभावित प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर। हालांकि, इस मॉडल का कुछ निश्चित सामाजिक–तकनीकी आधार हैं, जो परिष्कृत ब्ज पर निर्भर हैं। स्मार्ट शहर की कार्यसूचियां उत्सर्जन घटाने में प्रायःसहयोग देती हैं, जो व्यापक टिकाऊपन के लक्ष्यों का एक तत्व है।

पहुंच–सुगम शहर

पहुँच–सुगमता ; ।बबमेपइपसपजलद्ध माल अथवा सेवाओं तक लोगों की पहुंच की क्षमता है, जिसका मापन भौतिक दूरी, सामर्थ्य तथा औचित्य के लिहाज से उनकी उपलब्ध्ता के जरिए होता है। लेकिन पहुंच– क्षमता में सेवाओं तथा सुविधाओं, रोजगार के अवसरों, शिक्षा तथा आवास व्यवस्था के साथ–साथ उन तक पहुंचने के साधन भी शामिल हैं। शहरी संदर्भ में, घनत्व पहुंच को प्रभावित करने वाला एक कारक है, जैसी पड़ताल ऊपर हो चुकी है लेकिन हमें जुड़ाव, विविधता और तीव्रता पर भी विचार करना चाहिए; इन कड़ियों पर बाद में विचार किया जा रहा है। इसके अलावा,'पहुँच सुगम शहर' के हिस्सा के तौर पर भौतिक उपलब्धता से लेकर विकायत तथा सामाजिक–सांस्कृतिक तत्त्वों जैसे व्यापक आयामों पर भी विचार करने की जरूरत है। पहुँच–सुगमता (अभिगम्यता) व्यक्तियों की क्षमता को मानवता की भलाई के लिए जरूरी अथवा इच्छित क्रियाकलापों में शामिल होने से भी जुड़ा है। ऊपर की पक्तियों में घनत्व की समीक्षा में शहरी घनत्व तथा मानवीय तंदुरस्ती के बीच व्यवस्थित संबंध ढूंढने में कठिनाईयों का पता चला, जिनमें मिश्रित साक्ष्य, सघनता के विभिन्न पहलुओं के बीच व भीतर ताल–मेल की दिक्कत और मुद्दे का राजनीतिकरण शामिल हैं।

अभिगम्यता को सही अमल तथा नियोजन के एक उपयोगी औजार के रूप में देखा जाता है साथ ही सामाजिक तंदुरस्ती को बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में भी। हाल में, नवाचार व नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों तक सिर्फ भौतिक परिवहन के द्वारा ही नहीं पहुंचा जा सकता है। अतः, सुगमता स्थानों, लोगों, अवसरों व गतिविधियों तक पहुँच से जुड़ा है, वो भी भौतिक एवं आभासी जुड़ाव के तरीकों के द्वारा।

सामाजिक स्थायित्त्व से संबंध

सामाजिक स्थायित्व असमानता, विस्थापन, रहने की क्षमता और किफायती आवास व्यवस्था की जरूरत जैसी सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हे। टिकाऊ शहरों पर प्रारंभिक बहसें, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन अथवा घटी कार निर्भरता के माध्यम से सीमित पारिस्थितिक पदचिह्नों (फुटप्रिंट) से जुड़ी थीं। हालांकि, आजकल रोजगार, सेवाओं तथा शिक्षा, साथ ही साथ सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक संबद्धता तथा आर्थिक स्थिरता आदि सभी मुद्दे अधिक प्रासंगिक हो गये हैं। सामाजिक स्थायित्व तथा सुगम शहर की अवधारणाएँ एक–दूसरे को काफी ओवरलैप करती है।, चूंकि रोजगार, सेवाओं एवं शिक्षा, किफायती आवास, परिवहन, मनोरंजन सुविधाओं, औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थानों के लिए पहुंच एक प्रमुख मुद्दा है; साथ ही साथ सामुदायिक संबंध तथा सामाजिक आधारभूत ढांचा, जो सामाजिक समता तथा सामुदायिक स्थिरता पैदा करने में मदद करते हैं भी इससे जुड़ा है। सुगमता सामाजिक स्थायित्व के प्रक्रियात्मक पहलुओं से भी संबंधित है, जैसे कि विकास की प्रक्रियाओं में हितधारकों से संवाद एवं परामर्श तथा नीतियों एवं योजनाओं का जिम्मेदार प्रशासन एवं प्रबंधन एवं मानक निर्धारण की सामाजिक निगरानी सुगमता का मापन।

सुगमता, कई मायनों में घनत्व से कहीं ज्यादा व्यापक अवधारणा है और इसके मापन के लिए प्रायः नई विधियों का प्रयोग होता है। परिवहन तथा डिजिटल सुगमता के अंदर ही तीन तरीके सुझाए गये हैं:

1.डिजिटल सुगमता

2.जटिल शहरी प्रणालियों के मापन हेतु कंप्लेक्स नेटवर्क एनालिसिस (ब्छ।), जो सुगमता के लिए एक संकेतिक हो सकता है।

3.भौगोलिक सूचना व्यवस्थाएँ (जियोग्राफिक इन्फार्मेशन सिस्टम ळप्)। सुगमता (परिवहन) मापन का एक अनिवार्य उपकरण बन रहा है तथा यह लोगों के लिए शहरी अवसरों की सुगमता को लेकर विस्तृत जानकारी जुटा सकता है।

सुगमता के कई पक्षों के लिए, जैसी किफायती आवास, पारिस्थितिकध् सार्वजनिक स्थान आदि पर यह तरीके अपनाए जा सकते हैं। हालांकि,व्यापक आयामों– जैसे सामाजिक आधारभूत ढांचा अथवा न्याय और शक्ति पर अलग से विचार करने की जरूरत होगी।

'सुगम शहरों' की धारणा का दायरा परिवहन तथा गतिशीलता से कहीं व्यापक है, जैसा कि ऊपर की पंक्तियों में वर्णित है, यह सामाजिक स्थायित्व में योगदान से भी जुड़ा है। सबसे पहले इसमें आवश्यक श्रेणी के सार्वजनिक चीजें शामिल है। जैसे कि सार्वजनिक जगह, मेट्रो प्रणाली, श्रम बाजार, सड़कें, सेवाएं तथा हरित स्थान। साथ ही, सुगम शहरों के पास ऐसी सामाजिक आधारभूत संरचना होनी चाहिए, जो सामाजिक साम्यता (जिसमें सामर्थ्यशीलता शामिल है), और व्यक्तियों के विकास के लिए औपचारिक व अनौपचारिक संस्थानों की उपस्थिति हो तथा उन्हें सुगम बनाने को शक्ति और न्याय प्रणाली भी। अधिक संरचनात्मक तौर पर, सुगम शहरों में निवासियों के लिए उनकी सौदर्यबोध–विषयक गतिविधियों, मनोरंजनमूलक एवं जगह होने के भाव से जुड़े इच्छाओं एवं जरूरतों को पूरा करने के लिए भौतिक तथा पारिस्थितिकीय सार्वजनिक स्थान होना चाहिए। निम्नलिखित हिस्सा इन आयामों पर चर्चा करता है साथ ही पहुँच के मध्यस्थ के रूप में शक्ति एवं न्याय की भी।

संभवतः सुगम शहरों का सबसे स्पष्ट पहलू निकटता के जरिए जगहों तथा सेवाओं तक पहुंच है। इसकी सबसे पारिभाषित विशिष्टताओं में रिहाइसी तथा कार्यस्थल की सघनता, कार्यों का वितरण तथा मिश्रित उपयोग की कोटियों, केन्द्रीकरण का स्तर तथा स्थानीय स्तर की शहरी योजना शामिल हैं।

निवासियों के लिए सामाजिक संबंधों तथा बुनियादी दैनिक क्रियाकलापों तक पहुंच के लिए रिहाइसी निकटता सबसे मूल्यवान है। स्वीडेन में किये गये एक अध्ययन में 'सुगमता का विरोधाभास' पाया गया। हालांकि दस वर्षों की अध्ययन अवधि में स्थानिक सुगमता में सुधार के साथ स्थानीय व क्षेत्रीय दोनों स्तर पर औसत दूरी घट रही थी जबकि यात्रा की दूरी बढ़ गई । दूसरे शब्दों में, लोग को अपनी पसंद की सुख–सुविधा और रसद के लिए इच्छित दूरी से ज्यादा जाना पड़ा। यह पहुँच सुगमता के निर्धारकों तथा घनत्व, दोनों के प्रभाव के साथ संदर्भ तथा कार्यकारी तत्त्वों को समझने के महत्व को दर्शाता है।

सुगम शहरों को सभी शहरवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य –देखभाल जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाओं तक आसान पहुंच की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन हर एक संदर्भ में यह सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या ऐसी सभी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना स्थानीय शासन के लिए संभव है अथवा इनमें से कई ज्यादा अनौपचारिक तरीकों के जरिए मुहैया की जायेंगी।

अनौपचारिक आवासों में उच्चतम आवासीय घनत्व वैश्विक दक्षिण के बड़े शहरों के कई गरीबों की बस्तियों और झुग्गियों में पाए जाते हैं. रियो डी जेनेरियो, ब्राजील उच्च घनत्व झुग्गी–झोंपड़ियों (favela) और मध्य आय अपार्टमेंटों के बहुत ही सटे हुए जुड़ाव के मामले में विशिष्ट है (चित्र)।

परिवहन

जबकि निकटता जगहों तथा सेवाओं तक व्यक्तियों की पहुंच को निर्धारित करती है, परिवहन यह निर्धारित करने का मध्यस्थ है कि व्यक्ति उन गंतव्यों तक कैसे पहुंचें। एक लक्ष्य के रूप में सुगमता के साथ, लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के क्रम में –भूमि उपयोग तथा परिवहन–दोनों पर विचार किया जाना जरूरी है, अनिवार्यतः कारों पर ही नहीं। अतः शहरी क्षेत्रीय योजना निर्माण स्तर पर, सुगमता परिवहन तथा भूमि उपयोग योजना के एकीकरण हेतु एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है।

एक निश्चित हद तक, शहरी क्षेत्रों में यात्रा की गति बढ़ाकर भौतिक निकटता को हासिल किया जा सकता है। ढांचागत विशिष्टताएं, जो 'वेग द्वारा पहुंच' को प्राप्त करती हैं, उनमें सड़कों की व्याप्ति, सड़क तथा रेल नेटवर्क की गुणवत्ता तथा अन्य सार्वजनिक परिवहन संरचनाएं शामिल हैं।

निजी मोटर परिवहन कम घनत्व वाले कस्बाई विकास का अवसर देता है लेकिन सड़कों के लिए वहां कहीं अधिक भूमि की मांग होती है। यह स्थिति, सार्वजनिक परिवहन जो शहरी सघनता की मांग करता है तथा निजी कार उपयोग, जिसकी जरूरत जगह है, के बीच तनाव पैदा करती है।

शहर की परिवहन व्यवस्था इसके पर्यावणीय प्रभाव को भी प्रभावित करेगी। कार्बन उत्सर्जन का स्तर पूरी तरह परिवहन प्रणाली द्वारा निर्धारित होती है। 1970 से वैश्विक परिवहन उत्सर्जन में 80 फीसदी की वृद्धि सड़क पर चलने वाले वाहनों के कारण हुई है।

सामाजिक आधारभूत ढ़ाँचा

सुगम शहरों में सभी निवासियों को, परस्पर संपर्क, सामाजिक समूहों व संगठनों में शामिल होने तथा सामूहिक लचीलापन हासिल करने व आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामाजिक नेटवर्क निर्माण में समर्थ बनाने वाली सामाजिक संरचना भी होगी। आवासन कार्यकाल तथा पड़ोस का सामाजिक ढांचा प्रभावित करता है, कि निवासी वहां रहना पसंद करेगा या नहीं। लचीलेपन के लिए सामाजिक पूंजी ैवबपंस ब्वपजंसद्ध तथा नेटवर्क भी अहम होते हैं, इस लिहाज से, कि संकट या सदमे की स्थिति में वे सामाजिक समूह कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।

सामाजिक लचीलेपन के लिए विभिन्न तरह के सामाजिक नेटवर्क महत्त्वपूर्ण होते हैं, जिनमें से सामुदायिक समूहों की सदस्यता एक अहम पहलू है। अतः सुगम शहरों को इस बात पर भी विचार करना है कि शहर के स्वरूप व सामुदायिक सुविधाओं की स्थान–आधारित व्यवस्था, शहरी आबादी को सामाजिक नेटवर्कों तथा सामुदायिक समूहों तक पहुंचने को, समाज और व्यक्तियों के बीच संबंध बनाने की कैसी सुविधा देता है।

सत्ता व न्याय

पहुँच–सुगमता जोरदार रूप में शक्ति और न्याय से भी जुड़ा है कि ये इसे कैसे सुनिश्चित करते हैं कि सुगमता पूरी शहरी आबादी को हासिल है। शहरी विकास की राजनीति तथा अर्थशास्त्र से यह अर्थ निकलता है कि वंचित क्षेत्रों में पहुंच के संसाधन प्रायः निम्नस्तरीय होते हैं। ये विभेद भौगोलिक तौर पर स्थानीय संसाधन वितरण पर असर डाल सकते हैं, नतीजतन समाज के कुछ हिस्सों में पहुंच भेदभावपूर्ण हो सकती है तथा स्थानीय स्तर पर न्यायपूर्ण संसाधन वितरण सुनिश्चित करने की जरूरत पैदा कर सकती है। अतः इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे राजनीतिक व सांस्थानिक संदर्भ विकास को प्रभावित करते हैं।

सुगम शहरों में निश्चय ही, जाति, लिंग तथा आबादी समूह के अनुसार न्यायपूर्ण पहुंच की आवश्यकता होती है, साथ ही परिवहन जैसी सेवाओं तक पहुंच तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के बीच तालमेल के प्रति भी सजग होना चाहिए।

सत्ता एवं न्याय के लिहाज से पहुँच खासकर वैश्विक दक्षिण के शहरों में ;हसवइंस`वनजीद्ध अकसरः चुनौतीपूर्ण होती है। जहां यात्रा की लागत इसे रोकनेवाली है। परिवार ऐसी घरेलू रणनीतियों को अपना सकते हैं, जो एक या दो सदस्यों द्वारा यात्रा करने को वरीयता देती हों। यह अकसर लिंग तथा अन्य कारकों द्वारा भेद पैदा करता है, जिससे समाज के सिर्फ कुछ सदस्य ही कमाई के अवसर, शिक्षा तथा अवकाश की गतिविधियों तक पहुंच प्राप्त करते हैं। इसलिए, सत्ता व न्याय के मुद्दे किसी शहर के भौगोलिक क्षेत्रों, जाति, लिंग तक पहुँच को प्रभावित कर सकते हैं इसलिए इसकी आवश्यकता होती है कि योजनाओं को लागू करने के लिए समावेशी प्रशासन हो।

जैसे कि यहाँ इन्सेनाडा, मेक्सिको की तरह न्यूनतम आवासीय घनत्व विश्वभर के उच्च आय उपनगरों में पाए जाते हैं।

किफ़ायती आवास

ज्यादा घनत्व तथा किफ़ायती हाउसिंग टाईप वाले हिस्सों में किफ़ायती भाड़े वाली इकाइयां अधिक होती हैं बनिस्वत एक ही परिवार वाले घरों के कम घनत्व वाले हिस्सों के। जीवन जीने की लागतों तथा स्थितियों की विविधता सबों के लिए आकर्षक रहनवारी का निर्माण करेगी, जबकि उपयुक्त आवास तथा सेवाओं के अभाव के चलते लोगों को विशाल उपनगरों की ओर धकेला जाना संभावित हो जाता है। अंततः सुलभ आवास–व्यवस्था मात्र आवास के रूप पर निर्भर नहीं हैं क्योंकि इन्हें सुसंगत आवास संघ अथवा स्थानीय प्राधिकरण से सेवा की भी आवश्यकता होगी।

सामाजिक सांस्कृतिक आयाम

सुगमता आवागमन, सामाजिक संगठन अथवा रिहाइस के इलाकों पर 'आंतरिक रूप से' तथा बाहरी रूप से लागू होती है। कई शहर देश के अन्य हिस्सों से तथा विदेशों से बड़ी संख्या में लोगों के प्रवास का अनुभव कर रहे हैं। एक ओर तो यह उद्योग और श्रम शक्ति के लिहाज से बड़ा अवसर पेश करता है। दूसरी तरफ, किसी शहर में आने वाले हालिया प्रवासी प्रायः अधिक असुरक्षित हैं। सेवाओं तक बिना उचित पहुंच तथा बिना राजनीतिक आवाज के, संपत्ति व संसाधनों के अभाव के कारण मलिन दशा में रहते हैं। अतः शहरों के प्रशासन के सामने सुगमता के इन आयामों पर विचार की महत्त्वपूर्ण चुनौतियां हैं।

पारिस्थितिकीय तथा सार्वजनिक जगह

विश्व बैंक सार्वजनिक जगहों का वर्णन ऐसी जगह के रूप में नहीं करता कि, जो हो तो अच्छा हो बल्कि शहरों के लिए बुनियादी आवश्यकता के रूप में करता है तथा इनके लाभों को आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावणीय मूल्यों में विभाजित करता है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन संकेत करते हैं कि सार्वजनिक स्थान गरीबों की भलाई के साथ ही उनके समुदायों के विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनके पास निजी घरेलू स्थान नहीं होते हैं। अतः सार्वजनिक जगहें सुगम शहरों में समाविष्ट एक अहम घटक हैं तथा परिवहन, पानी और स्वच्छता आदि के समान्तर इन्हें एक सेवा समझा जाना चाहिए।

नवाचार व व्यवसाय

सुगम शहरों में व्यक्तियों को आर्थिक अवसरों के साथ–साथ शहरों तक गैर–भौतिक पहुंच के लिए तकनीक के उपयोग की क्षमता की भी गुंजाइश मिलती है। सर्वप्रथम, यह देखा गया है कि श्रम–शक्तियों तथा विस्तृत बाजार क्षेत्रों को अधिक सुलभ बनाने से भौतिक संपर्क ज्ञान निर्माण प्रक्रिया को तेज करता है।

दूसरे, यदि शहरों को 'स्मार्ट विकास' के मॉडल अपनाने हों तो, प्रोद्योगिकी तक पहुंच अनिवार्य है। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी का तेज और व्यापक, प्रसार हो रहा है, जो शहरी नेटवर्क के जुड़ाव को बढ़ाता है लेकिन यह स्थानिक तौर पर असमान है।

ICT और इंटरनेट समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। अतः भौतिक परिवहन, प्रौद्यौगिकी तक बढ़ी पहुंच शहरी नागरिकों के लिए भलाई को बढ़ावा दे सकती है लेकिन इससे असमानताओं को बढ़ने का डर भी है।

सुगमता तथा शहरी स्वरूप–सुगमता क्या जोड़ती है?
सुगमता के आयामों का शहरी घनत्व के पहलुओं के साथ गहरा संबंध है लेकिन वे शहरी घनत्व की दलीलों की कमियों को भी संबोधित करते हैं

तथा शहरी विकास में नवीनता जोड़ते हैं। निश्चय ही घनत्व के जरिए पहुंच बनाना संभव है। उच्च घनत्व सीधे जगहों तथा सेवाओं तक निकटता बढ़ाता है जिससे त्वरित परिवहन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, मिश्रित भूमि उपयोग ओर घनत्व जैसे शहरी तत्वों की मौजूदगी का स्थानीय सेवाओं व सुविधाओं तक पहुंच तथा उपयोग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि कुआलालंपूर तथा पुत्राजाया में साबित हुआ। हालांकि, सघनता भी पहुंच को कम कर सकती है, उदाहरण के तौर पर जहां उच्चतर घनत्व के साथ किफायती आवास की संभावना घट जाती है। अतः सुगमता शहरी विकास की बारीकियों को सीधे संबोधित करती है, जिसमें न्याय एवं शक्ति तथा शहरी रूपाकार में प्रौद्योगिकी का समावेश शामिल है। जहां, पहुंच के स्थान आधारित तथा परिवहन पक्षों पर आधारित सुगमतां परस्पर आव्यापन ;वअमतसंचद्ध करते है, यह अवधारणा नये आयाम प्रस्तुत करती है, जो टिकाऊ विकास में योगदान देते हैं। सुगमता के विशिष्ट योगदान निम्नानुसार हैंः

1. सबसे पहले, घनत्व के विपरीत अभिगम्यता इस बात पर ध्यान देता है कि क्या हो, क्योंकि इसकी परिभाषा, न सिर्फ जगहों तक पहुंच वाले बल्कि रोजगार, अवसरों तथा सेवाओं तक पहुंच बनाने बल्कि इसके द्वारा तंदुरस्ती (well-being) को बढ़ावा देने वाले की हैं। यह प्रक्रियात्मक पहलुओं समेत अधिक सामाजिक स्थायित्व की विमर्शों के साथ एक खास तरह का परस्पर–व्यापन (overlapping) करती है।

2. परिवहन, सुगम शहरों का एक प्रमुख घटक है, जिसमें 'वेग द्वारा पहुंच' की धारणा शामिल है तथा जिस तरह से विभिन्न परिवहन रूप इसमें योगदान करते हैं। इस तरह यह विभिन्न शहरी विकास के प्रतिमानों को आर–पार करती ;बतवे.बनजद्ध है।

3. सुगमता में सामाजिक आयाम भी जोरदार ढंग से शामिल हैं, इस नजरिए से कि सामाजिक व्यवस्था शहरी नवीकरण तथा स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि जो पहुंच प्राप्त करता है, अहम है इसलिए सत्ता व न्याय के आयामों(प्रक्रियात्मक) का यह समावेश करता है।

4. इससे यह भी जुड़ा है कि पहुंच का निर्धारण व्यक्तियों की परिसंपत्तियों तथा सामाजिक नेटवर्कों द्वारा होता है, और इस तरह सुगम शहर स्पष्ट रूप से समता की चिंताओं तथा हाशिए के लोगों पर विचार करते हैं; खासकर भौगोलिक रूप से तथा सामाजिक तौर पर असमावेशित ;मगबसनकमकद्ध लोगों पर। इसके कुछ पहलुओं में अंतरशहरी चुनौतियों पर ध्यान दिया जायेगा जैसे कि किफ़ायती आवास आदि जबकि, अन्य में शहर में योगदान देने आ रहे लोगों हेतु अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण पर ध्यान दिया जायेगा।

5. सुगम शहर डिजिटल पहुंच को अपनाते हैं तथा नवाचार ;पददवअंजपवदद्ध के लिए स्थितियों का सृजन करते हैं।

भविष्य का अनुसंधान एजेंडा

हलाँकि यह अध्याय सुगम शहरों पर केन्द्रित है, शहरी घनत्व फिर भी कुछ मामलों में उपयोगी मापक तथा संकेतक है।

- ऐसे बेहतर संकेतकों की आवश्यकता होती है, जो इन विभिन्न घटकों को पकड़ में ले सके, खासकर भीड़ वाले तथा जहाँ के आँकड़े कम उपलब्ध है, वहाँ के लिए।

- हमें इस बात की व्यापक समझ की आवश्यकता है कि कैसे, शहरी स्वरूप लोगों के अपने इलाकों से जुड़ाव को तथा रिहाइस, सार्वजनिक सुविधाओं तथा रोजगार और सेवाओं से निकटता, के बीच तालमेल की उनकी प्राथमिकता को प्रभावित करते हैं।

- कम उपयोग की गयी भूमि की स्थिति तथा विस्तार को लेकर अधिक जानकारी की आवश्यकता है, चाहे परित्यक्त हरीतिमा–विहीन जमीन, पसरे क्षेत्र अथवा ऊंचे मूल्य वाली इमारतें हों। इसी तरह, यह अस्पष्ट रहता है कि क्या वहां शहरी स्थायित्त्व के आयामों के बीच तालमेल बैठेगा। शहरी सुगमता को लागू करने में अधिकतम लाभ पाने के क्रम में सामान्य सुगमता तथा हरित जगहों तक पहुंच के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए और अधिक अध्ययन आवश्यक होगा।

- असमानता को बढ़ाये बिना प्रौद्योगिकी अथवा तेज परिवहन तक पहुंच बनाने के लिए ऐसे विकास के न्यायमूलक प्रभाव पर केन्द्रित अध्ययन होना चाहिए। जैसा कि मेडलिन, कोलंबिया में देखा गया कि गरीबी घटाने तथा टिकाऊपन के बीच सह–अस्तित्व संभव है, और इन सह–अस्तित्त्वों का आगे भी पता लगाया जाना चाहिए।

- घनत्व के लिए, अभी भी अधिकतर प्रमाण दनिया के उत्तरी भूभाग ;हसवइंस दवतजीद्ध से आते हैं, जबकि सत्ता और न्याय के इर्द–गिर्द स्थायित्त्व से जुड़े आयाम, किफायती आवास,परिवहन विकास की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध ;हसवइंस वनतजीद्ध में पूरी तरह भिन्न है। इसलिए, विभिन्न संदर्भों में तुलनात्मक अध्ययन यह समझने के लिए महत्त्वपूर्ण होगा कि सुगम शहर कैसे विकसित हो सकते हैं और सकारात्मक पथ पर पहुंच सकते हैं।

- इसके अतिरिक्त, सुगम शहरों को लेकर शोध में 'ग्रह–व्यापी शहरीकरण'पर विचार करने की जरूरत है, जिसमें शहरीकरण के नये स्वरूप शामिल हैं जो शहरियत की आवधारणाओं को चुनौती दे रहे हैं।

- सुगमता के सभी आयामों पर विचार करने के क्रम में, शहरी जीवन को उद्धाटित करने वाली श्रेणियों, विधियों तथा मानचित्रण पर भी ध्यान देना चाहिए।

- अंततः सुगम शहरों के लक्ष्यों को न्यायपूर्ण तथा हरित शहरों के पक्षधरों के साथ देखा जाना चाहिए। समग्र रूप से टिकाउ शहरी व्यवस्था प्राप्त करने के लिए, सुलभ, हरित तथा न्यायपूर्ण शहरों के सभी आयामों पर एक दूसरे के साथ विचार करना चाहिए तथा तालमेल और सहयोगों का भी आकलन किया जाना चाहिए।

3. हरित शहर

डेविड सायमन

19 वींसदी के अंत से, शहरी योजना–निर्माण एक पेशे के रूप में औद्योगीकरण के शुरुआती चरणों में इसके हानिकारक प्रभावों के मुद्दों के सम्बन्ध में सोचती रही है। तब से स्वास्थ लाभ और तंदुरस्ती के लिए खुले स्थानों की आवश्यकता एक केन्द्रीय मुद्दा रही है।

इंग्लैण्ड में इसके परिणामों में एक यह था कि पहले से बन्द शाही पार्क आम जनों के लिए खोल दिए गए और विभिन्न खेलों जैसे फुटबॉल, से जुड़ाव को बढ़ावा,उदाहरण स्वरुप नई पिचों और सुविधाओं का निर्माण करके, दिया गया। मैदानी (आउटडोर) शौक लोकप्रिय हुए उदाहरण के तौर पर जो स्काउट आन्दोलन द्वारा प्रदान किए गए।

योजना जल्द ही रिहाइशी इलाके को औद्योगिक या वाणिज्यिक इलाकों से अलग करने पर केन्द्रित होने लगी। 20वीं सदी के आते ही उद्यान शहरों के विकास में तेजी आई। ऊलीवल हेगबी का निर्माण ओस्लो में हुआ। 1910 के दशक के मध्य में अंग्रेजी उदाहरणों को रोल मॉडल के रूप में इस्तेमाल करें तो गोथेनबर्ग में, लंदाला इग्नेहेमसौमरेड ;स्ंदकंसं ग्दीमउवतंकमकद्ध का और एक दशक बाद औग्रिंटट्रैडगार्ड्स टेड का निर्माण प्रारम्भ हुआ।

हालाँकि शहरी योजना का विकास उसका बस एक हिस्सा है जिसे आज वैश्विक स्तर पर 'टिकाऊ शहर' कहा जाता है।

वैश्विक दक्षिण ;ळसवइंस ैवनजीद्ध1 शहरी योजना और टिकाऊ शहरी विकास को अक्सर पश्चिमी विश्व द्वारा चुनौतियों का सामना करने हेतु विकसित अवधारणाओं के रूप में देखा जा रहा है। अन्य देशों, जैसे दक्षिणी अफ्रिका, में स्थानान्तरित होकर इन्हें इसके बदले सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है। प्रकृति संरक्षण के मुद्दों में अधिक सहभागिता में निवासियों की आवाजें और जानकारियाँ केवल बाद के चरणों में शामिल हुईं ह्यू पैरनेल द्वारा लिखित चौथा अध्याय देखें। निम्न आय क्षेत्रों में अक्सर हरित क्षेत्रों का अभाव है जो अधिक संपन्न क्षेत्रों के पास है. हरीतिमा विहीन धरती सार्वजनिक स्थानों पर निवेश और देखरेख का अभाव दर्शाती है।

टिकाऊपन की बहसों का एक बहुत ही कम विमर्शित लेकिन अहम पहलू कमजोर वोल ॅ;मांद्ध और अधिक जोर ेेजतवदहद्ध टिकाऊपन के बीच का अंतर है। ब्रंड्टलैंड कमीशन रिपोर्ट (1987) के बाद टिकाऊपन पद को विस्तृत प्रकार के सन्दर्भों में इस्तेमाल किया जाने लगा। एकदम क्षीण हालतों में इसका इस्तेमाल बिना किन्हीं वास्तविक सुधारों के मौजूदा गतिविधियों को उचित ठहराने के लिए किया जाने लगा, जो 'ग्रीनवाश' के रूप में जाना जाने लगा। मजबूत टिकाऊपन पहल कदमियाँ कारणों, चलाने वालों और सत्ता के सम्बन्धों को सम्बोधित करती हैं जबकि कमजोर पहल कदमियाँ मौजूदा प्रणालियों और सम्बन्धों के क्रमिक परिवर्तनों को सन्निहित करती हैं. मजबूत पहल कदमियों के उदाहरण शहरों में वाहन यातायात को कम करने के लिए पादचारीकरण योजनाओं से जुड़े हुए सुलभ वहनयोग्य जन परिवहन में निवेश हैं।

हरित अर्थव्यवस्था

कई सन्दर्भों में हरित अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा हो चुकी है। इसका महत्व सतही से आत्यंतिर रूप में बदलता रहता है जहाँ मुख्य मुद्दा आर्थिक विकास और टिकाऊपन के बीच संतुलन से जुड़ा होता है। बहुत ही चरम हालातों में यह सामाजिक संरचना में मौलिक परिवर्तनों की माँगों तक ले जा सकती है। हालाँकि, वर्तमान में प्रबल प्रवृत्ति मुख्यतः टिकाऊपन को बढ़ावा देनेवाली नव उदार रणनीतियों और उनके अवसरों के बचाव की प्रतीत होती हैं।

हरित अर्थव्यवस्था अब और एक राष्ट्रीय मामले के रूप में नहीं विकसित हुई है। शहर और अन्य गैर–राष्ट्रीय संगठन न केवल प्रतिभागी हुए हैं बल्कि कई मामलों में राष्ट्रीय रणनीतियों के विकास में पहलकदमी की है और उन्हें प्रेरित किया है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और प्रशामक चुनौतियों को सुलझाना एक मुख्य शहरी प्राथमिकता बन गया है चूँकि विशेष रूप से कारण और प्रभाव दोनों असुरक्षित शहरी क्षेत्रों के लिए गंभीर खतरे पैदा करते हैं. पारिस्थितिक तन्त्र सेवाएँ और शहरी हरित रणनीतियों को कार्य के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में देखा जाता है।

वैश्विक दक्षिण में एक हरित अर्थ व्यवस्था और विकास की रणनीतियों में अक्सर वृद्धि और परिवर्तन दोनों के तत्व रहते हैं। भीषण बेरोजगारी और निम्न आजीविका को कम करने के लिए वृद्धि आवश्यक है। ऐसे दृष्टिकोणों में टिकाऊ समाज और टिकाऊ शहरों में एक उचित पारगमन सन्निहित है। यह 'हरित' से टिकाऊ समाजों के दो अन्य पहलुओं– पहुँच और न्याय– के सम्बन्ध को स्पष्ट करता है।

आपदा संकट की कमी और जलवायु परिवर्तन

आपदा संकट की कमी और जलवायु परिवर्तन से निबटने के काम की विभिन्न उत्पत्तियाँ हैं लेकिन हाल के वर्षों में वे एक–दूसरे से मिल गई हैं खासकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सम्बंधित असुरक्षा को कम करने और प्रतिरोध में सुधार करने के मामले में शोध की पदावली में 25 वर्षों की एक अवधि में समाज विज्ञानों और गैर–अकादमिक ज्ञान के ज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ तेजी से यह काम शुद्ध रूप से वैज्ञानिक होने से अंतर्विषयक और पारविषयक होने तक भी विकसित हुआ।

जलवायु परिवर्तन को दो स्पष्ट तरीकों से अभिव्यक्त किया जाता है। मौसम की अत्यधिक तीव्र स्थिति, जो तेजी से बराबर तथा और अधिक गंभीर परिणामों के साथ हो रही है (आपदा संकट की कमी से इसका जुड़ाव स्पष्ट है) और धीमे परिवर्तन जैसे समुद्री जल स्तर में वृद्धि। इन दोनों अभिव्यक्तियों का सीधा असर शहरी क्षेत्रों पर है खासकर उनके आर्थिक महत्व के लिए। कई मामलों में, आवश्यक पहलकदमियोंऔर रणनीतियों की जिम्मेदारी भी स्थानीय या क्षेत्रीय हैं। खासकर इन कारणों से इस क्षेत्र में स्थानीय अधिकारी तेजी से सक्रिय हो गए हैंदृ चाहे पूर्ण स्वतंत्र रूप से या कई स्तरों पर भागीदारी और अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता के साथ।

केन्द्रीय लागोस, नाइजेरिया के अनौपचारिक व्यापारी जो अपने अस्थायी व्यापार को बढाने के लिए अपने स्टॉल की जगह के शोर और प्रत्यक्ष असुविधा के बावजूद रहते हैं।

डकार, सेनेगल का यह मिनी बस का आखिरी पड़ाव (टर्मिनस) महानगर के इस हिस्से का एक मुख्य पहुँच वाला केन्द्र है जो वहनयोग्य मोटर परिवहन से भिन्न जगहों को जोड़ता है।

हरित शहर–एक मन्त्र से कहीं अधिक

हरित शहरों से सम्बंधित विमर्शों और पहलकदमियों के आधार के तौर पर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक और व्यावहारिक प्रभावों के साथ कोई सीधा सम्बन्ध चिन्हित कर पाना दुर्लभ है।

- 'ऊपर से पहलकदमियाँ और निदेश
- पहलकदमियाँ और गतिविधियाँ जो 'समानांतर रूप से' विकसित होती हैं उदाहरणस्वरुप सहयोगी संस्थाओं में जैसे सी 40 ;ब्40द्ध2 और आई सी एल इ आई ;प्ब्स्म्प्द्ध3
- समर्थकों के द्वारा अक्सर प्रेरित आंतरिक गतिविधियाँ जिनके महत्व को कम नहीं आँका जाना चाहिए.

शहरों के विश्लेषण करने का एक तरीका यह है कि उनके आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय पहलुओं को उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं, परिप्रेक्ष्यों और सन्दर्भों से जोड़ा जाए। इन तीन व्यवस्था परिप्रेक्ष्यों पर आधारित करके 'शहरी हरितकरण' पद पर विचार किया और परखा जा सकता है।

एक सामाजिक–आर्थिक पद्धति के साथ विभिन्न पहलकदमियों के मूल्य से लेकर आधारभूत संरचना, तकनीकी और नई नौकरियों में निवेश तक हरित अर्थ व्यवस्था के आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है। अध्ययनों की एक बड़ी संख्या संकेत देती है कि 'हरित' कंपनियों और संगठनों में नई नौकरियों की संख्या क्रमिक रूप से बन्दकिए गए पुराने, प्रदूषणयुक्त उद्योगोंमें चली गई नौकरियों की संख्या की तुलना में कहीं अधिक है। सामाजिक–आर्थिक पद्धति नव उदारवादी और मिश्रित आर्थिक सिद्धान्तों के साथ अक्सर जुड़ी होती है लेकिन विशेष क्षेत्रों में उन पद्धतियों को भी शामिल करती है जो टिकाऊपन में योगदान दे सकते हैं जैसे, भवनों का रोधन, निर्माण के लिए जीवाश्म मुक्त तकनीकी का विकास और फैला हुआ शहरी और – शहरी अर्धशहरी खाद्य उत्पादन जो नौकरी एवं और अधिक सुरक्षा पैदा करते हैं.

सामाजिक–आर्थिक पद्धति विशेष रूप से जिलावार या शहरवार हस्तक्षेपों का आकलन करने के लिए उपयुक्त है जहाँ तकनीकी नवाचार नए, टिकाऊ और हरित हलों को पैदा करना और साकार करना संभव करता है। ऐसे परिस्थिति सम्बंधित शहरोंया स्मार्ट शहरों के साथ अक्सर विस्तृत वाणिज्यिक विपणन होता है और होते हैं स्थानीय मेयर और राजनीतिज्ञ जो टिकाऊपन के मुद्दे पर अपनी अग्रगामी स्थिति का प्रदर्शन करना चाहते हैं।

षोध की शब्दावली में, परिस्थिति सम्बंधित शहरों या स्मार्ट शहरों की पहलकदमियों को कुछ शक की नजरों से देखा जाता है और टिकाऊ और न्यायसंगत शहरों के विकास में उनके योगदान पर प्रश्न खड़े किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में और इनके माध्यम से प्राकृतिक व्यवस्थाओं और संसाधन आवाजाही के मामले में सामाजिक–पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य का इस्तेमाल बहुत ही व्यापक तरीके से किया गया है। सारे शहर भले उनका आकार कुछ हो, हवा, पानी, खुले स्थानों और वनस्पति पर निर्भर हैं। औद्योगिक युग के दरम्यान हालाँकि इन परिसम्पत्तियों के मूल्य को इस हद तक कम आँका गया कि प्रदूषित जल, क्षीण हवा और मनोरंजन के अवसरों की कमी के कारण आदमी की सेहत एकदम खराब हो गई है।

हाल के वर्षों में इन मुद्दों की समझ और ज्ञान में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्रों में मानव को जो सेवाएँ प्रकृति देती है उनको आँकने के लिए पारिस्थितिक तन्त्र सेवाओं के अध्ययन बहुत ही समान उपकरण बन गए हैं। इसलिए पारिस्थितिक तंत्रों का रख–रखाव और वृद्धि भी सामाजिक–पर्यावरणीय तंत्रों में प्रतिरोध क्षमता का आधार बनते हैं। प्रचंड घटनाओं और अन्य परिवर्तनों का सामना करने के लिए प्राकृतिक छलनियों और बाँधों का जीर्णोद्धार अक्सरनई आधारभूत संरचनाएँ बनाने से अधिक योग्य साबित हुआ है। यह अन्य फायदों की ओर भी ले जा सकता है जैसे बढ़ा हुआ जैविक वैविध्य, शहरी खाद्य उत्पादन के लिए बेहतर अवसर, ग्रीनहाउस प्रभाव में कमी और निवासियों के लिए मनोरंजन के उन्नत अवसर।

हरित शहर पहलकदमियाँ – स्थान–संबंधी वर्गीकरण

शहरी हरितकरण की छतरी तले पहलकदमियों के विविध फैलाव को वर्गीकृत करने के कई संभव तरीके हैं। भौगोलिक पैमाने पर आधारित एक प्रारूप वर्गीकरण जो लघु से व्यापक के रूप में व्यवस्थित है, नीचे प्रस्तुत है।

पैमाने के सबसे छोटे सिरे की पहलकदमियाँ, छोटे भवन, भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उदाहरण के रूप में काम करते हैं और पहलकदमियों के समेकित प्रभाव में योगदान देते हैं. अधिकतर पहलकदमियाँ स्वैच्छिक होती हैं हालाँकि कभी कभी अनुदानित होती हैं। इनमें निम्न–ऊर्जा बल्ब, सौर पैनलों को स्थापित करना, घरेलू कूड़े कचरों को वानस्पतिक खाद बनाना और साइकिलों तथा जन परिवहन का बढ़ता इस्तेमाल शामिल है।

सामूहिक खरीद और निर्णय से एक खंड या किरायेदार–स्वामी संगठन पैमाने का अर्थ–प्रबंधन कर सकता है।

तीसरा स्तर एक क्षेत्र, एक उपनगर या जिला है जहाँ स्थानीय अधिकारी रणनीति से सम्बंधित निर्णय ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर जिला को गर्म करने में निवेश। यह भी है जहाँ मुख्य पुनर्विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सकता है, उदाहरण के तौर पर जब घरों और नए व्यापारों की राह निकालने के लिए पूर्व के जहाज निर्माण या औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जाता है या उन्हें नष्ट कर दिया जाता है।

टिकाऊपन के परिप्रेक्ष्य से उस भूमि पर जो पहले से निर्मित था शहरी विकास श्रेयस्कर है. क्योंकि जल, निकासी एवं अन्य सेवाएँ पहले से ही अपनी जगह पर हैं,अन्य क्षेत्र से जोड़ने का व्यय औसतन कम पड़ता है। हालाँकि ग्रीनफील्ड स्थलों पर यदि शहरी सेवाओं को प्रति निवासी या प्रति क्षेत्र इकाई की दर जोड़ा जाए तो नया भवन निम्नतर घनत्व और उच्चतर व्यय देता है।

हालाँकि ऐसी अधिकाँश समग्र पुनर्विकास योजनाएँ, उदाहरण स्वरुप गोथेनबर्ग में अल्वास ट्रैंडम, मुख्य रूप से मध्यवर्गीय निवासियों को लक्षित करते हैं, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है. ये परियोजनाएँ इसके लिए अच्छे अवसर प्रदान करती हैं कि एक मजबूत टिकाऊपन खाका प्रतिबिंबित हो जो न्याय को बढ़ावा देता हो और ये जर्जर क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में योगदान दे सकती हैं और आकर्षक क्षेत्रों तक पहुँच को बढ़ावा दे सकती हैं।

अगले स्तर पर, जो सम्पूर्ण शहर, एक स्थानीय प्राधिकार या एक बड़ी व्यवस्था में कई स्थानीय प्राधिकार हो सकता है, ऐसी योजनाओं जैसे ऊर्जा क्षमता वृद्धि, हरित आधारभूत संरचना या कूड़ा–कचरा पुनरावर्तन की नीतियों और रणनीतियों के लिए पहलकदमी कर सकता है. इस पैमाने पर, संयुक्त कार्य के मिश्रित फायदे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन यह स्थानीय संतुलन और शक्ति एवं उत्तरदायित्व के वितरण पर भी निर्भर करता है।

अंत में, जैव भौतिक प्रक्रियाएँ (जैसे देश और शहर, नदियों और बाँधों का संतुलन स्थापित करना), आर्थिक विकास और संसाधन उपयोग के मामले में शहरी क्षेत्र सबसे पैमाना बनते हैं। हालाँकि ऐसे एक क्षेत्र को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तरों के बीच सुसंगत सीमाओं और शक्तियों के साथ जैसे एक जिला प्रशासनिक बोर्ड, जिला काउंसिल या क्षेत्र, किसी प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

हरितशहर, शहरी हरितकरण और हरित, टिकाऊ शहरों को बढ़ावा देने के लिए बढ़ता समर्थन कई स्थानिक कार्यसूचियों पर प्रधानता से दिखलाई दे रहा है. प्रारम्भिक तौर सबसे ऊपर यह समृद्ध देशों में दिखलाई पड़ रहा है लेकिन यह तेजी से विश्वव्यापी हो रहा है। ऐसे कार्यक्रमों और पहलकदमियों का उपयोग निःसंदेह कभी–कभी वाणिज्यिक हितों के लिए किया जा सकता है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए एक बड़ी चुनौती इन हितों को जहाँ तक संभव हो जनता के फायदे से जोड़ना है। सारे स्तरों पर हरित कार्यसूचियाँ प्रोत्साहनों और उद्देश्यों का एक जटिल मिश्रण दर्शाती हैं।

फिर भी, प्रगतिशील पहल कदमियों और कार्यवाईयों के लाभों के कई उदाहरणों में मुख्य संभावनाएँ अन्तर्निहित हैं. चाहे इन्हें सीधे जलवायु परिवर्तन को कम करने या उनसे अनुकूलन के लिए या शहरों को उनके निवासियों के लिए अधिक आकर्षक रूप में रहने के लिए उठाया गया हो।

यह कई स्थानीय सरकारों के संकुचित सरकारी पूंजी और सीमित क्षमता के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है और इसलिए समुचित उपायों को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए मजबूत औचित्य प्रदान करता है।

यहाँ पेश किए गए कई बदलावों के कार्यान्वयन के अवरोधों में एक विश्व के कई हिस्सों में पुराने शहर योजना कानून हैं। ये 20 वीं सदी के मध्य के दिशा–निर्देश हैं जो उस समय के सिद्धान्तों और मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं जो समकालीन शहरीकरण की जटिलताओं और गतिकी एवं और अधिक निर्धन शहरी निवासियों की व्यावहारिक आवश्यकताओं के लिए अनुकूल नहीं है।

हालाँकि विशेषकर पिछले निवेशों और औद्योगिक मंदी के कारण बदलाव को कार्यान्वित करना कठिन भी है और अधिक समय लेनेवाला भी। यह सच है भले ही शहरी ऊर्जा व्यवस्था में टिकाऊपन बेहतर करने और शहरी और सीमान्त–शहरी कृषि विकसित करने और शहरी हरितकरण के अन्य प्रकार की आवश्यकता सर्वविदित और स्वीकार्य दोनों है। केवल वर्तमान नियमों को लागू नहीं करने से, उदाहरणस्वरुप सार्वजनिक स्थानों पर खेती को स्वीकृति देकर,स्वयं ही नवीनीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण समर्थन हो सकता है।

ऐसे समाजों में जहाँ निजी संपत्ति अधिकार पवित्र हैं, कई व्यक्ति सरकारी नियमों और 'हस्तक्षेप' को नापसंद करते हैं, भले ही ये सामाजिकचुनौतियोंके सम्बन्ध में हों. राजनीतिक प्रतिबद्धता, पूर्व के निवेशों और मजबूत हित–समूहों से जुड़कर यह क्रमिक हरित हस्तक्षेपों से मौलिक रूपांतरणकारी परिवर्तन की यात्रा को एक कठिन चुनौती बना देता है।

आम तौर पर किसी न किसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित पर्यावरणीय मुद्दे हालाँकि राजनीतिक कार्यसूची में तेजी से बढ़े हैं, कभी कभार ही वे निर्णायक चुनावी मुद्दे बने हैं. हालाँकि, विश्वभर में स्थानीय प्राधिकार महत्वपूर्ण हरितकरण उपायों के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में सक्षम हुए हैं। ये हरितकरण उपाय भवनों और खुले स्थानों दोनों के लिए हैं जो पृथक्करण से ऊर्जा बचत, मानकों, वर्षा जल के अन्तःसरण और तेजी से फैलनेवाले प्रतिकूल वनस्पति प्रजातियों के नियंत्रण तक फैले है। इसके बराबर ही महत्वपूर्ण निवासियों के लिए स्थानीय अनुदान एवं अन्य प्रोत्साहन हैं जिससे कि वे भी इसमें स्वयंशामिल हो सकें। इसमें सौर पैनलों को स्थापित करना, विदेशी के स्थान पर देशी प्रजातियों की खेती करना, शावर और डिशवाटर के पानी को सींचने के लिए फिर इस्तेमाल करना, छोटी सैर के लिए सायकिल का इस्तेमाल करना या कार पूल और जन परिवहन का उपयोग करना हो सकते हैं।

साख और दूकानदारी दोनों के लिए निजी फर्मों का टिकाऊपन के लिए विभिन्न उद्योग मानकों का स्वैच्छिक पालन करना महत्वपूर्ण हो गया है. उदाहरणस्वरुप इंग्लैण्ड में बी आर इ इ एएम (विश्व का सबसे पुराना मानक, 1990 में स्थापित) भवनों के लिए एक वैश्विक मानक और कई अन्य देशों में समान प्रमाणी करणों के लिए मॉडल बन गया है।

अन्त में, शहरी योजना में प्रकृति की भूमिका पर चेतावनी के दो बोल. इसमें छिपा हुआ और कुछ हद तक मुखरित विचार यह है कि प्रकृति को शहर और इसकी योजना के लिए वश में या अनुकूल कर लिया जाए। इसमें कुछ काम हो सकते हैं जैसे शहरों के किनारों पर गीली जमीनों और समुद्र तटों की हिफाजत करना। ऐसे कई क्षेत्रों का इस्तेमाल फुर्सत के क्षणों या मनोरंजन के लिए किया जाता है, उसी प्रकार घास भरे क्षेत्रों का उपयोग खेलकूद के लिए किया जाता है। हालाँकि, 'प्राकृतिक' क्षेत्र के रूप में उन्हें संरक्षित करने के लिए कुछ स्थानों में लोगों का प्रवेश वर्जित करने की भी एकप्रवृत्ति है। यदि विशेष तौर पर असुरक्षित प्रजातियाँ या पारिस्थितिक तन्त्र शामिल न हों तो ऐसीअनयता की अनदेखी की जा सकती है। प्रकृति को मानवीय गतिविधियों से अलग नहीं किया जाना चाहिए।

पर्यावरणीय रूप से नवाचारी शहर बनाने की अपनी कोशिशों में शहरी डिजायनर प्रकृति–छवि लैंडस्केप आर्किटेक्ट मानव संस्कृति की अनदेखी नहीं कर सकते। समाज की समस्याओं का उत्तर अविकृत प्रकृति में ढूँढने का हर प्रयास प्रकृति को उस रूप में देखने का प्रयास है जैसी यह है या मानवों की पूर्ण अनुपस्थिति में थी। फिर भी योजना अपरिहार्य है और कोई भी परियोजना चीजों को उस हालत में वापस नहीं ला सकती जैसा वे मानवों के आने के पहले थीं।

औद्योगिक प्रदूषण और गैर टिकाऊ नगरीकरण से निबटने के लिए व्यापक पुनर्विकास के हिस्से के रूप में शहरी आधारभूत संरचना हरीतिमा।

4. न्यायपूर्ण शहर

सुसान पारनेल

2015 के यू एन सस्टेनेब्ल गोल्स (SDGs) ने इस विचार को सामने रखते हुए कि लोग चाहे कहीं भी हों उन्हें सार्वभौमिक रूप से प्रयुक्त किए जाने वाली इच्छाओं की कामना करनी चाहिए कि इनमें इस और आनेवाली पीढ़ियों में 'कोई पीछे न छूटें', अपनी वैश्विक मूल्यों में एक मोड़ लाया. हमें पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को कई स्तरों पर समझने की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र का नया शहरी लक्ष्य (नं0 11) शहरों को समावेशी, सुरक्षित, टिकाऊ और लचीला बनाने का उद्देश्य रखता है।

टिकाऊ विकास के लिए ये हिस्से एक दूसरे पर निर्भर हैं। लक्ष्य 11 को प्राप्त करने के लिए यहाँ तक कि निर्धन और असमान शहरों में जिस प्रकार (खास तौर पर धनवान) रहते हैं उसे धरती के लिए कम हानिकारक बनाना है।

2015 के बाद कार्यसूची की सबसे बड़ी चुनौती न्याय को वैश्विक रूप से अनुकूलित करना है और विश्व भर के सारे शहरी निवासियों को समान निम्नतम नियम और सुरक्षा प्रदान करनी है। वर्तमान में इसका कोई तर्क नहीं कि शहरी निवासियों की पूर्व, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए न्याय के अलग–अलग संस्करण हों। साधारण सा तर्क है– सारे शहरी निवासी समान हैं और उनकी रक्षा की जानी चाहिए।

लेकिन वास्तविक रूप से उन शहरों में क्या किया जा सकता है जहाँ असमानता और अन्याय का वास है? यह अध्याय एक परिवर्तन प्रक्रिया का वर्णन करता है जो एक ऐसे विचार, जो शहरों में एक अधिक न्यायपूर्ण भविष्य के निर्माण की कामना रखता है, की अवधारणा , रूपरेखा और कार्यान्वयन को समन्वित करती है।

पहला केन्द्रीय उद्देश्य है रूपरेखा, संस्कृति और प्रशासन के मामले में शहरों के अन्याय को कम करने की कोशिश करना। यह अध्याय शहरों पर केन्द्रित है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उचित विकास को निश्चित रूप से किसी स्थानीय प्रशासन द्वारा उत्पन्न और नियंत्रित किया जाए। यह उद्देश्य केवल एक याददिहानी है कि एक और अधिक न्यायोचित विश्व के निर्माण को कार्यान्वित करने के लिए स्थानीय प्रशासनों के पास अबतक आवश्यक शक्तियाँ और संसाधन नहीं है.।

क्या न्यायोचित है इसकी अवधारणाएँ विभिन्न शहरी विचारों और व्यवहारों से सम्बन्धित हैं और वे समान रूप से न्याय को परिभाषित नहीं करतीं। बात न्याय के एक विचार को दूसरे के विरुद्ध रखने की नहीं है बल्कि इस बात के महत्व को रेखांकित करते हुए शुरुआत करने की है कि शहर के सम्बन्ध में विविध मूल्यों के बारे में हम किस प्रकार से सोचते हैं और तब हम उन मुख्य कारवाईकर्ताओं और उपकरणों को परिभाषित करें जो शहरों में मूल्य–आधारित हस्तक्षेपों को विकसित कर सकते हों।

शहरी विकास के व्यापक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्थानिक सन्दर्भ के महत्व को स्वीकार करते हुए, यू एन–हैबिटैट (UNHABITAT) अब राष्ट्रीय शहरी विकास योजनाओं के विचार को आगे बढ़ा रहा हैं। ऐसा यह हैबिटैट (HABITAT III) की तैयारियों के माध्यम से एस डी जी गोल 11 को साकार करने के लिए आवश्यक वचनबद्धताओं को कार्यान्वित करने के एक साधन के रूप में कर रहा है। SDGs और HABITAT III शहरी जीवन की गुणवत्ता में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय असंगतियों के साथ सारे शहरों के लिए एक वैश्विक कार्यसूची परिभाषित करने के एक प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आस–पास के सैद्धांतिक मतभेदों के अलावा शहरों में पुनर्वितरण और सामाजिक सुरक्षा में सरकारों से समुचित रूप से अपेक्षा की जानी चाहिए कि उच्च, मध्य और निम्न आय सन्दर्भों में न्याय और समानता की अवधारणाओं के उपयोग में स्पष्ट अन्तर भी हैं। इस बात पर भी विवाद के महत्वपूर्ण बिन्दु हैं कि न्याय और समानता के सम्बन्ध में किस प्रकार राज्य की भूमिका को देखा जाए ।

पश्चिमी विश्व भर में वर्तमान में इस बात की निश्चितता संकट में है कि सरकारें न्यायपूर्ण शहरों के प्रबंधन को संभाल सकती हैं। यहाँ तक कि सम्पन्न समाजों में भी शहरी वातावरण, खासकर निर्धनों के लिए, बिगड़ गया है. इसलिए एक न्यायपूर्ण शहर की दृष्टि को पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

वैश्विक दक्षिण (Global South) में प्रारम्भिक बीसवीं सदी में निर्मित वातावरण में शहरी योजना और सार्वजनिक निवेश शहर के सबसे असुरक्षितों की हालत की मुख्य रूप से अनदेखी करते हुए केवल विदेशी और स्थानीय अभिजात वर्ग के हितों की पूर्ति करते थे। विकासशील देशों के लिए वैश्विक समर्थन के उदय से यह स्थिति सीमित तरीकों से बदली, उदाहरण के तौर पर विशेष परियोजनाओं के माध्यम से बुनियादी आवश्यकताओं जैसे जल और सफाई व्यवस्था या आवास तक पहुँच प्रदान कर। इस सदी में केवल बाद में शहरी सामाजिक सुरक्षा और शहरी निर्धन अपनी आजीविका को बेहतर करने के लिए स्वयं क्या कर सकते थे, पर तात्कालिक रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया ।

वैश्विक दक्षिण में ऐसे शहरों की संख्या अब बढ़ रही है जिनके पास न्याय और समान मूल्यों पर आधारित सामाजिक सुरक्षा है हालाँकि यह असमान रूप से वितरित है। अब शहरी योजना के सामूहिक लाभों में एक फिर से उपजी दिलचस्पी भी है। हालाँकि शहरी निवासियों के अधिकाँश हिस्से के लिए यहाँ तक कि अल्पतम अधिकारों की प्राप्ति में अभी बहुत देर है। बहुत सारे नगरों और शहरों में यहाँ तक कि अत्यधिक बुनियादी घरेलू सेवाओं तक के स्तरों का अभाव जारी है जो शहरी निर्धनों के अवसरों को पंगु कर दे रहा है।

इस बात पर कोई आम विद्वतापूर्ण सहमति नहीं है कि एक शहर में न्याय का अर्थ क्या हो सकता है या न्याय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। न ही एक 'न्यायपूर्ण शहर' का कोई सार्वभौमिक मॉडल है, हालाँकि यह संभव है कि परोक्ष रूप से एस डी जी इस आधार रेखा को परिभाषित कर देगा जैसे कि HABITAT III में 'शहर को अधिकार' पर विमर्श एक वैश्विक मानक का निर्माण कर सकते हैं।

अलग अलग स्थितियाँ, शहर में शेअर बाजार दलाल, लन्दनय कोपेनहेगन में भिखारीय मापुटो के बाजार में खरीदार और व्यापारी।

आज के शहरी वातावरण में बढ़ती विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए, यह उपयोगी हो सकता है कि न्यायपूर्ण शहरी विकास की पूर्ववर्ती विचारधाराओं पर गौर किया जाए और इस पर भी कि किस प्रकार ये आदर्शवादी विचार शहरी प्रबन्धन की बदली हुई विधियों से मेल खा सकते हैं खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ शासन और प्रशासनिक शासन पद्धति पश्चिमी यूरोप से भिन्न हैं, जहाँ व्यापक पैमाने के वितरण की कई विधियाँ विकसित हुईं।

21वीं सदी में शहरों के लिए आदर्श विचारधाराएँ

वर्तमान और भविष्य के शहरों को सुधारने का अवधारणात्मक काम अपना ध्यान निवासी पर केन्द्रित करता है। हालाँकि आबादी के बढ़ने और खपत ने बहुत सारे पर्यावरणशास्त्रियों को यह मानने पर विवश कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तन्त्र का विनाश जिस प्रकार शहरी निवासी रहते हैं उसके कारण होते हैं और हमें प्राकृतिक व्यवस्था में मानवों की भूमिका के बारे में और अधिक सचेत होना चाहिए। इस व्याख्या में, न्याय का पद ज्यादा पर्यावरणीय पदचिन्ह, अंतरपीढी समानता और अंतरप्रजातीय सहनिवास के बारे में है। हालाँकि राजनीतिक पर्यावरणशास्त्री भविष्य के हल के रूप में शहरों को ही नहीं नकार देते लेकिन वे मूल्य–आधारित शहरी प्रबंधन और नवाचारी विधियों के माध्यम से शहरों को बदलना चाहते हैं।

कई शहरवादियों, इसमें उनको भी शामिल कर लें जिनके लिए अर्थव्यवस्था के बदले पर्यावरण न्याय का आधार है, के लिए यह शहरी निवासियों की एक रोजाना आधारभूत संरचना तक पहुँच है जो न्याय पैदा करती है। यह केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह है जो शहर पर नागरिक के अधिकार को पहले से मानकर चलती है जहाँ भेदभाव से मुक्ति शहरी जीवन और संस्कृति में प्रतिभागिता को सक्षम बनाती है।

कुछ लोगों का मानना है कि एक न्यायपूर्ण शहर के निर्माण की शुरुआत इन बुनियादी सवालों को संबोधित कर होती है कि शहर को किन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। जो भी सन्दर्भ हो शहरी पैमाने पर न्याय संरचना, अधिकारियों और संस्थानों के बीच परस्पर क्रिया पर आधारित है। यूरोपीय सन्दर्भ में, जिस प्रकार से बहुत ही हाल में शहर में अन्याय को अभिव्यक्त किया गया है वह प्रवासियों, हाशिए पर के लोगों, समूहों के अ–समावेश के माध्यम से जाहिर हुआ है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य (लैंगिकता, जातीयता और भाषा को शामिल करते हुए भेद–भाव के विभिन्न प्रकारों पर अंशतः आधारित) केवल सेवाओं की उपलब्धता नहीं, पहुँच और वितरण के मुद्दों को देखने का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है.। एक यूटोपियाई आदर्श के रूप में शहर का अधिकार न्याय की अवधारणा को चार तरीकों से सामने रखता है।

1. हथियाई हुई जमीन को वापस लेने के लिए यह एक पूर्वशर्त है।

2. यह सम्पूर्ण शहर के लिए एक रणनीति है न कि केवल व्यक्तियों और परिवारों के लिए।

3. यह मानता है कि झुग्गी–झोंपड़ी क्षेत्र या हाशिए पर के पड़ोस स्थानीय शासन की एक समूची व्यवस्था में समाहित होते हैं।

4. यह आश्रय के सार्वभौमिक अधिकार की माँग करता है।

SDGs और HABITAT III एक न्यायपूर्ण शहर को क्या आवश्यक है इस पर अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं लेकिन आज के सामाजिक विकास के लिए एक और अधिक न्यायपूर्ण शहरी भविष्य हेतु अवधारणात्मक और राजनीतिक ढाँचे के रूप में सबसे अधिक स्वीकृति सामाजिक अ–समावेश और शहर पर अधिकार की ।

शहरों को बदलने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं और कुछ समृद्धि की स्थितियों के लिए बेहतर रूप से उपयुक्त हैं तो कुछ अत्यधिक निर्धनता के सन्दर्भ के लिए. और अधिक न्यायपूर्ण बनने के लिए किस प्रकार शहर अपने को बदलने की कोशिश करते हैं इस पर आधारित अधिक व्यावहारिक सामग्री हस्तक्षेप के चार सामान्य क्षेत्रों को चिन्हांकित करती है।

1. शहरी योजना
2. कल्याण या सामाजिक सुरक्षा
3. नागरिकों की प्रतिभागिता
4. हाशिए के समूहों की स्वयं की कार्रवाई.

कभी–कभी ये एक–दूसरे से प्रतिद्वंदिता करते हैं और कुछ मामलों में एक हल दूसरे से बेहतर काम करता है। लेकिन 'एक न्यायपूर्ण शहर' को साकार करने के लिए ये साधन एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं।

यूटोपियन आदर्शों को बढ़ावा देने और न्यायपूर्ण शहर बनाने के उपकरण

व्यक्तियों या समूहों की शहर में न्यायपूर्ण ढंग से प्रतिभागिता करने की क्षमता को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। ये कल्याण (भोजन, पानी, धन) सुनिश्चित करने के बुनियादी कारकों से लेकर अपराध से मुक्ति और स्वतंत्रता से घूमने फिरने या पर्यावरणीय सुरक्षा का उपभोग करने के अधिक जटिल कारकों तक फैले होते हैं।

न्यायपूर्ण शहरों को बढ़ावा देने के सारे हस्तक्षेपों में बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस बात के स्पष्ट रूप से गहरे राजनीतिक और वित्तीय निहितार्थ है कि विभिन्न कारकों को किस प्रकार का महत्व दिया जा रहा है। प्रत्येक रणनीतिक निर्णय को अपनाए गए उपायों को कार्यान्वित करने में समर्थ होने के लिए संस्थानात्मक समर्थ्न की भी आवश्यकता होती है।

शहरी योजना

शहर स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण जगहें नहीं हैं। भूमि और श्रम के बाजार वर्तमान और भविष्य के निवासियों को असमान लाभ प्रदान करते हैं। हालाँकि, किस प्रकार शहरों की रूप रेखा तैयार की जाती है, उनका प्रबंधन किया जाता है और उन्हें चलाया जाता है, उनसे समावेश और अ–समावेश के प्रकारं प्रभावित होते हैं। यह और कहीं भी और उतना प्रत्यक्ष नहीं है। जितना अफ्रिका, एशिया और लैटिन अमेरिका के तेजी से विकसित होते शहरों में है। यहाँ बेहतर योजना क्षमता वाले शहर कमजोर योजना वाले शहरों की बनिस्बत वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने और फलने–फूलने में अधिक सक्षम प्रतीत होते हैं। वे वैश्विक योजना प्रणालियों को अंशतः ऑवरलैप करते हैं, यहाँ तक कि उनसे प्रतिद्वंदिता करते नजर आते हैं. हालाँकि, किसी शहर में सक्षम योजना किसी प्रकार से यह सुनिश्चित नहीं करती कि जनता की आवश्यकताओं को न्यायपूर्ण तरीके से संबोधित किया जा रहा है. और इसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है कि सामाजिक योजना जनता की बेहतरी की पूर्ति करती है।

इसलिए कौन एक न्यायपूर्ण शहर योजना की मशीन को चला सकता है? इसका पारंपरिक उत्तर स्थानीय सरकार है हालाँकि कई शहरों (बड़े देशों जैसे केन्या और भारत को भी इसमें शामिल कर सकते हैं) में इस स्तर पर उचित लोकतांत्रिकता या कार्यरत प्रशासन का अभाव है। बिना एक सक्षम नगरपालिका व्यवस्था

– और एक स्थानीय अभिजात वर्ग के, जो उन निहित स्वार्थों, जो शहरी राजनीति पर अक्सर छाए रहते हैं, से ऊपर उठकर निर्धनों और वंचितों के हितों को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है, शहरी प्रबंधन के प्रभावकारी और समावेशी व्यवहारों को प्राप्त करना लगभग असंभव है।

हालाँकि, इसमें अन्य लोग भी हैं जो न्यायपूर्ण शहर की कार्य सूची को चला सकते हैं और शहरी नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते हैं। अमेरिका और वैश्विक दक्षिण के मामले में, जहाँ समाजवाद की उतनी महत्वपूर्ण परम्परा नहीं है जितना यह यूरोप या ऑस्ट्रलेशिया में है, अक्सर यह राष्ट्रीय सरकार और मजबूत नागरिक समूह और कम्पनियाँ हैं जो विकास और पुनर्वितरण कार्यसूचियों को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण शहरी कार्यान्वयक हैं।

एक न्यायपूर्ण शहर को प्राप्त करने के लिए सरकार, समुदायों और निजी क्षेत्र में सक्षम प्रशासकों और पेशेवरों का रहना जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही उनकी मिलकर काम करने की क्षमता। कई शहरों के लिए समस्या यह है कि यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्य कर्ता कौन हैं. शायद इसलिए कि निजीकरण या आउटसोर्सिंग ने उनकी भूमिका को ढँक लिया है या फिर यह हुआ है कि संसाधनों को आबंटित करने या वितरित करने के दौरान पारंपरिक अधिकारियों या नागरिक समाज की भूमिका को ना मान्यता दी गई ना इनका प्रवेश हुआ।

इस बात को सुनिश्चित करने का कोई एकमात्र रास्ता नहीं है कि किसी शहर में न्याय का व्यवहार होता है। सिंगापुर जैसे कुछ शहरों ने योजना को सशक्त करके और शहरी वृद्धि प्रक्रिया का कठोरता से प्रबंधन करके महान प्रगति की है. अन्य शहरों, जैसे पोर्टो एलेग्री और क्यूरिटिबा ने शहरी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में प्रतिभागी योजना पर बल दिया है। हालाँकि, ये भिन्न उदाहरण इस बात को प्रगट करते हैं कि ऐसी गतिविधियाँ जो पारदर्शी और निर्भरयोग्य हैं किसी प्रक्रिया के न्यायपूर्ण होने में विश्वास प्रदान करते हैं।

सामान्य दक्षिण पूर्वी एशियाई मॉडल, जिनके पास मजबूत भूमि उपयोग नियंत्रण हैं, दर्शाते हैं कि शहरी क्षेत्रों में गतिविधियों की सघनता आर्थिक विकास के लिए बेहतर संभावनाओं, सार्वजनिक सेवा और अधिक किफायती वितरण और विशेष पर्यावरणीय चुनौती का सामना करने की और अधिक बड़ी गुंजाइश की ओर ले जाती है। यह दक्षिण एशिया के एकदम उलटा है जहाँ शहरों ने आवासन और सेवाओं की घटी हुई दर में सामाजिक एकीकरण को सरकार की सहायता के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए अपना ध्यान केन्द्रित किया है। लेकिन यहाँ भी अ–समावेश को कम करने में थोड़ी सफलता मिली है। पिछले 15 वर्षों के दरम्यान शहरी निर्धनता और असमानता दोनों का स्तर नीचे गया है। योजना विधियों के ये विरोधाभासी उदाहरण दर्शाते हैं कि किस प्रकार शहरी योजनाकर्ता न्यायपूर्ण शहरों को प्राप्त करें इसके लिए कोई अंतिम रूप रेखा नहीं है लेकिन संसाधनों के साथ सरकारों की सम्मिलित कार्रवाइयाँ एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकती हैं।

प्रभावकारी शहरी विकास और योजना को आवश्यक रूप से बहुत ही सन्दर्भ–संवेदनशील होना चाहिए. ऐसी कोई एक नीति नहीं हो सकती जो सब पर लागू हो जाए. पहले की पृथक ऊपर से नीचे की योजनाएँ कई सन्दर्भों में कारगर नहीं हुई हैं. हालाँकि UNHABITAT के अनुसार, ऐसे चार योजना हस्तक्षेप हैं जिनके बारे में व्यापक रूप से समझा जाता है कि वे एक मंच प्रदान कर सकते हैं जहाँ से एकीकरण और न्याय को बढ़ावा दिया जा सकता है. ये हैं–

बुनियादी सेवाएँ और आधारभूत संरचना

बुनियादी आवश्यकताएँ जैसे सुरक्षा, पानी और स्वच्छता और सामाजिक सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक देखभाल तक पहुँच को बेहतर करने में सघन रूप से रहना सामान्यतः प्रति व्यक्ति और अधिक आसान और सस्ता बनाता है। हालाँकि बड़े शहरों की यह प्रवृत्ति है उन आधारभूत संरचना को प्राथमिकता दे जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हो या राजनीतिज्ञों को मतदाताओं के सामने लोकप्रिय बनाती हों. इस प्रकार अक्सर व्यय दूरसंचार और आवागमन का बुनियादी ढ़ाँचा (Connectivity Infrastructure) जैसे बन्दरगाह, मोटरों का रास्ता, एयरपोर्ट इत्यादि 'संपर्क आधारभूत संरचनाओं' की ओर चला जाता है। यह लोगों के लिए बुनियादी आधारभूत संरचनाओं, जिससे शहरी नागरिकों के एक बड़े हिस्से को लाभ होता, के बदले में किया जाता है। न्यायपूर्ण शहरों का निर्माण ऐसी शहरी नीतियों को आवश्यक बनाता है जो बड़ी आधारभूत संरचनाओं, सामाजिक व्यय और क्षेत्र–विशिष्ट हस्तक्षेपों जैसे आवासन में निवेश को एक समग्र कार्यसूची के हिस्से के रूप में एकीकृत करती हों जिससे सारे निवासियों की पहुँच सम्पूर्ण शहर तक हो सके।

सार्वजनिक परिवहन

सबको अर्थव्यवस्था में भाग लेने के समान अवसर प्रदान करने के लिए परिवहन सेवाओं और आधारभूत संरचना जैसे सड़कें, पैदल पथ, बस पथ एवं अन्य आवागमन तरीकों में निवेश के माध्यम से सम्पूर्ण शहरी आबादी की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है। शहरी यातायात नीतियों में असफलता निर्धनों को महत्वपूर्ण रूप से संकटग्रस्त अवस्था में छोड़ देती है क्योंकि वे लम्बी दूरी तक आने जाने का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते और अक्सर बुरे ढंग से अवस्थित क्षेत्रों या सीमान्त में रहते हैं।

शहरी संपत्ति और आवासन

आवासन (रहवास) और संपत्ति एक बड़ी सीमा तक निवासियों की इस क्षमता को तय करती हैं कि वे कहाँ रहना चुनें और इस प्रकार उनकी बचत करने और सामाजिक विकास में योगदान करने की क्षमता को भी तय करती हैं। इस क्षेत्र की नीतियों का इस बात पर असर पड़ता है कि एक शहर किस प्रकार एक जीने योग्य सामुदायिक जीवन को बनाए रखता है, शहरी जीवन में अप्रवासी समूह का समावेश करता है और टिकाऊ शहरी विकास के लिए रणनीति विकसित करता है।

आवासन में अपर्याप्त पहुँच गरीबी और अ–समावेश के एक दुष्चक्र, खास तौर पर अप्रवासियों और निर्धन निवासियों के लिए जो अक्सर अस्थायी आवासन पर निर्भर रहते हैं, को बढाता है। अवधि की अस्थिरता का अर्थ यह भी है कि नगरपालिकाओं को अक्सर कम कर राजस्व प्राप्त होते हैं और इस प्रकार वे आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में असमर्थ हो जाते हैं. तब सेवाओं को अन्य स्रोतों से प्राप्त करना होता है जो अक्सर इन्हें और खर्चीला बना देता है।

इस बात की और अधिक जागरूकता की जरूरत है कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय अ–समावेश को रोकने के लिए शहरी योजना एक सशक्त उपकरण है। वर्तमान में जो मुख्य कमियाँ हैं खासकर वैश्विक दक्षिण के शहरों में, उनसे निबटने के अधिक अनियोजित हस्तक्षेपों, जो शहरों को न्यायपूर्ण जगहं बनाने में मदद करेंगे को अधिक स्थान देने की आवश्यकता को अंधेर में नहीं धकेलना (ओवरशेडो) चाहिए। इनमें से बहुत महत्वपूर्ण वे व्यापक पैमाने के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हैं जो विशिष्ट रूप से राष्ट्रीय सरकारों द्वारा वित्तपोषित है।

शहरी सामाजिक सुरक्षा तन्त्र

वैश्विक उत्तर में, शहरों और देशों के बीच कल्याण समर्थन के पैकेज में भारी विषमता है लेकिन विशिष्ट रूप से उनमें बेरोजगारी भत्ता, आवासन सहायता, पेंशन, बाल समर्थन, निःशुल्क या अनुदानित स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं का एक विस्तार है। सहायता के लिए प्रशासनिक प्रबंध भिन्न हो सकते हैं लेकिन सरकार और गैर सरकारी संगठनों से वैकल्पिक सेवा देनेवालों के अलावा विशिष्ट रूप से स्थानीय सरकारें एक अहम् भूमिका अदा करती हैं।

वैश्विक दक्षिण में, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक बीमा, बाल सुरक्षा, इत्यादि जैसे सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक नीतियों का एक व्यापक फैलाव है। पिछले दशक में पूरे विश्व के कई देशों में सामाजिक सुरक्षा के इन प्रकारों का विकास इस बोध को दिखलाता है कि राज्य को बाजारों को आकार देने, विकास के लाभों का पुनर्वितरण करने और मानव पूँजी और निर्धन के कल्याण में उचित निवेश सुनिश्चित करने में एक और अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए सामाजिक क्षेत्र में फिर से लगने की आवश्यकता है।

एक बड़ी या छोटी सीमा तक अधिकाँश शहर सामाजिक सुरक्षा के काम में लगे हैं और यदि यह एक अच्छे तरीके से हो जाता है, अ–समावेश की दरों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. सामाजिक सुरक्षा के उपाय न केवल गरीबी को कम करते हैं और आय–विसंगतियों को घटाते हैं, वे मानव पूँजी और उत्पादकता को भी बढाते हैं और अन्य की अपेक्षा कुछ शहरों को बहुत ही न्यायपूर्ण स्थान बनाते हैं।

यहाँ तक कि निम्न आय क्षेत्रों में भी एक बोध हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा उपायों का अपना एक महत्व है। लैटिन अमेरिका, अफ्रिका और पूर्व एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के नगरों में सामाजिक सहायता कार्यक्रमों में एक व्यापक फैलाव हुआ है। वैश्विक दक्षिण के शहरों में सामाजिक सुरक्षा उपायों को अनौपचारिक क्षेत्रों को समर्थन करना है जहाँ अधिकाँश निर्धन शहरी निम्न आय वाली, असुरक्षित नौकरियों में हैं। औपचारिक क्षेत्र में भीं इसे गति देने के लिए स्थानीय अधिकारी लोगों के द्वारा अपने व्यापारों को औपचारिक रूप देने के लिए कीमत को कम करने और लाभ को बढाने के लिए अपने कानूनों और नियमों को अनुकूल कर सकते हैं।

निष्कर्ष

समय के साथ शहरीकरण ने सामान्य रूप से समाजों को और अधिक न्यायपूर्ण एवं और अधिक समान कर दिया है लेकिन इसके बावजूद शहर स्वयं असमान और अन्यायपूर्ण जगहों के रूप में रह गए। इसके अनेकों कारण हैं कि देशों, क्षेत्रों और पूरे विश्व में शहरों में इतनी भारी असमानताएँ क्यों हैं। सारे शहरों में भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय शक्तियाँ हैं. इसलिए उन्हें और अधिक न्यायपूर्ण बनाने में दीर्घकालिक राजनीतिक कार्य की आवश्यकता है।

सारे शहरों के पास एक से पर्यावरणीय संसाधन नहीं हैं जो इस बात को प्रभावित करता है कि शहरों के बीच पानी, ऊर्जा और भोजन जैसी सेवाएँ कैसे गतिमान होती हैं। न ही एक शहर में सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का न्यायोचित वितरण केवल वर्तमान की माँगों पर केन्द्रित रह सकता है. इसे भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी अवश्य देखना होगा।

षहरी असमानता और निर्धनता को समझने के लिए उन आर्थिक शक्तियों को भी समझना आवश्यक है जो शहरी जीवन को आकार देते हैं और उसकी संरचना करते हैं। पूँजी और श्रम के प्रवाह जो शहरों को खिलाने या भूखा रखने की क्षमता रखते हैं; वैश्विक औए राष्ट्रीय नियामक शक्तियों जैसे व्यापार समझौतों, सूद दरों और उत्पाद मानकों से अत्यंत प्रभावित होते हैं।

असमान रूप से वितरित प्राकृतिक संसाधनों, अपने भिन्न इतिहासों और पूँजी के असमान वैश्विक और राष्ट्रीय प्रवाहों, जो कुछ शहरों में नौकरियाँ पैदा करते हैं और अन्य में नहीं के कारण शहर न्यायपूर्ण नहीं हैं। नौकरियों और अन्य आर्थिक अवसरों तक न्यायपूर्ण पहुँच बढाने में शहरों के हस्तक्षेप भविष्य के न्यायपूर्ण शहरों का निर्माण करने के कुछ बहुत ही बुनियादी साधनों में हैं।

शहर इसलिए भी न्यायपूर्ण नहीं हैं क्योंकि अभिजात समूह अपने हितों की रक्षा करते हैं और करों में अपने योगदान को कम से कम कर देते हैं जिनपर सामाजिक पुनर्वितरण निर्भर होता है। शहरों में न्यायपूर्णता नहीं होना जातीयता, उम्र, लैंगिकता, धर्म और भाषाई पूर्वाग्रह,इत्यादि का फल भी हो सकता है। शहरी समाजों के बहुत ही अधिक गंभीर फॉकों में एक युवा लोगों और अप्रवासियों का हाशिए पर होना भी है।

शहरी न्याय की प्राप्ति में कई स्तरों (वैश्विक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय) पर और विभिन्न कर्ताओं (सरकारें, प्राधिकार और निजी क्षेत्र) से कार्रवाई की आवश्यकता है। न्याय में एक आम सहमति निहित है जो दूसरों की माँगों को मान्यता देती हो और सार्वजनिक हितों को निजी हितों के आगे रखती हो। शहरी आदर्शवादी विचारों की एक समृद्ध विरासत है जिससे हम बहुत कुछ ले सकते हैं और हमें लेना चाहिए जब हम नवाचारी रूप से एक सामूहिक एवं और न्यायपूर्ण शहरी भविष्य के बारे में सोच रहे हों।

5. निष्कर्ष, परिणाम एवं व्यावहारिक दिशा निर्देश

हेनेरिटा पामर और डेविड सायमन

समग्र और टिकाऊ शहरों को हासिल करने के लिए, सुगम्य, हरित और न्यायपूर्ण शहरों के सारे आयामों पर एक दूसरे के साथ विचार करने, उन्हें सन्दर्भ के साथ व्यवस्थित करने और सह–क्रिया एवं तालमेल के लिए उनका मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता है।

टिकाऊ विकास के तीन आयाम हैं: सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय टिकाऊपन। वे एक दूसरे की मदद करते हैं लेकिन उनमें कई द्वन्द भी गुँथे हुए है।

- आर्थिक और सामाजिक टिकाऊपन के बीच – निजी और सरकारी के बीच
- आर्थिक और पर्यावरणीय टिकाऊपन के बीच– लोगों और प्रकृति के बीच
- सामाजिक और पर्यावरणीय टिकाऊपन के बीचः उदाहरण के तौर पर जब वैश्विक उत्तर के द्वारा वैश्विक दक्षिण में पर्यावरणीय सुरक्षा की माँग आर्थिक विकास और सार्वजनिक निवेशों को बाधित करती है।

यह पुस्तक 'आर्थिक' को एक अलग अंश के रूप में छोड़ते हुए 'सुगम', 'हरित' और 'न्यायपूर्ण' जैसी अवधारणाओं का अन्वेषण करती है। क्या ये अवधारणाएँ नए शक्ति संघर्षों की ओर ले जाती हैं या वे शहरी वातावरण में टिकाऊ विकास के लिए अवसरों के द्वार खोलती हैं?

टिकाऊ विकास की परिभाषा स्थानीय व्यवहार और स्थानीय परम्पराओं के साथ ही स्थानीय संघर्षों और दृष्टिकोणों में भिन्नताओं के माध्यम से बदलती है। इसलिए अवधारणा के तीनों आयामों की लगातार परीक्षा होती है और उनपर फिर से काम किया जाता है, जो उनके लिए दी जानेवाली दलीलों को और जोरदार भी बनाता है।

क्या हम इस बात पर जोर डाल सकते हैं कि इसका वर्णन एक सैद्धांतिक रूपरेखा के रूप में करने से पहले टिकाऊ विकास को स्थानीय रूप से सामने लाया जाए? इस पुस्तक के मुख्य अध्यायों के तीन लेखक मानते हैं कि शहरी टिकाऊपन को समझने और संभवतः उसे साकार करने के लिए स्थानीय सन्दर्भ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, एक संभव निष्कर्ष स्थानीयता को टिकाऊ विकास के एक चौथे और महत्वपूर्ण आयाम के रूप में रेखांकित करना होगा।

निष्कर्ष

टिकाऊ विकास के सिद्धान्त और व्यवहार के बीच के अंतर को संघर्षों के बीच समझौते पर काम करके और साथ–साथ शहर में टिकाऊ विकास क्या होगा इसकी दृष्टि को बढ़ावा देकर दूर करने की आवश्यकता है।

अध्याय 2 में जेम्स वॉटर्स सघनता की सुस्थापित अवधारणा को लेकर आगे बढ़ते हैं। हालाँकि वे घनत्व के टिकाऊ विकास के एक एकमात्र माध्यम के रूप में होने पर सवाल खड़े करते हैं और सुगमता के पक्ष में घनत्व के पुनर्निरुपण की सलाह देते हैं। सुगमता मुख्य रूप से गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन तक पहुँच के बारे में, विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक स्थान, हरित क्षेत्र, किफायती आवास और सामुदायिक सुविधाओं तक पहुँच के बारे में और सामाजिक तन्त्र और सामुदायिक समूहों तक पहुँच के बारे में है।

शहरी विकास का कार्यान्वयन करने के लिए, सुगमता का उपाय उत्तम व्यावहारीकरण और योजना के लिए एक अच्छा मापक है, साथ ही यह सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने का एक माध्यम भी है। हालाँकि, कई दुविधाएँ विरोधाभास भी पैदा कर सकती हैं, उदाहरण के तौर पर विकसित सार्वजनिक परिवहन और हरित, निर्माणमुक्त स्थानों की आवश्यकता के बीच की दुविधा।

सुगमता की अवधारणा का विस्तार अन्य आयामों जैसे जानकारी, ज्ञान या अनुभव तक पहुँच के साथ किया जा सकता है। स्थानीय ज्ञान और अनुभव को एक ब्द2–शून्य भविष्य में परिवर्तन को निर्मित करने के लिए प्रयुक्त होने में समर्थ करने के लिए, सुगम्य शहर को ज्ञान के विभिन्न स्रोतों तक पहुँच को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सुगमता शहरी नागरिकों और शहर के बीच एक सम्बन्धात्मक अवधारणा है और ज्ञान तक पहुँच अपने शहरी वातावरण के साथ नागरिकों के सीधे सम्बन्ध और अंतर्क्रिया को बढ़ावा देता है।

हरित शहर के लिए भी न्याय एक मौलिक मार्गदर्शी सिद्धान्त है। हरित शहर का पश्चिमी उद्गम एबनेजर हावर्ड ;म्इमद्रमतक भ्वूंतकद्ध के उद्यान शहर (गार्डेन सिटी) में है लेकिन उद्यान शहर ने उन समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जिनसे आज के हरित शहर जूझ रहे हैं. आज जलवायु परिवर्तन सबसे विकट चुनौती है जो हरित शहर को कार्य सूची में पीछे ढकेल दे रहां है। हालाँकि बिना एक ऐसे सामाजिक कार्य सूची के जलवायु परिवर्तन से निबटा या इससे बचा नहीं जा सकता है, जो न्याय और समानता को भी शामिल करता है।

वैश्विक वातावरण के लिए दूसरी 'नई' चुनौती मधुमक्खियों के द्वारा परागन और अन्य समान प्राकृतिक कार्यों का सफाया है जिसने नई पारिस्थितिक तन्त्र सेवाओं को उत्पन्न किया है।. हालाँकि कभी कभी वे एक प्रकार के विनिमय में अधिकतर परिवर्तित हो जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, पेड़ों के एक झुरमुट, जिसे हटा दिया गया है, को हरी छतों से बदला जा सकता है। झुरमुट के सौन्दर्य, छाँव, सूक्ष्म–वातावरण, पहचान और ऐतिहासिक जुड़ाव जैसे मूल्यों की जगह ऊँचे–ऊँचे भवनों की छतों पर सेडम पौधे की 'अदृश्य' कालीनों के साथ एक कार्यमूलक हरीतिमा–समीकरण ;निदबजपवदंस हतममदपदह मुनंजपवदद्ध से अवस्थापित किया जाता है।

'विकृतियों या भ्रष्ट परिणामों'(देखें अध्याय 3) की ओर बढ़ने के अलावा यह परिभाषा की इस दुविधा को दर्शाता है कि चूँकि हम किसी चीज का नामकरण कर सकते हैं तो इसे संख्या–आधारित (परिमाणात्मक) रूप में देखा जा सकता है। दूसरी ओर, गुणात्मक मूल्य संख्यात्मक मापन पर आधारित नहीं होते हैं जैसा कि झुरमुट का उदाहरण दिखलाता है।

हालाँकि ये द्वन्द पूर्व में विचारित विकास के द्वन्द के साथ जुड़ जाते हैं जहाँ पर्यावरणीय आधुनिकीकरण सामाजिक विकास के पहले अभिजात आदर्शवादी दृष्टि को रखता है। हम टिकाऊ विकास को बढ़ावा देते हुए विरोधी अवधारणाओं के लिए नए मतैक्य (अध्याय 3) प्रस्तावित करते हैं।

टिकाऊ विकास को एक मानदंड संबंधी दिशा देने के लिए यदि 'सुगम' और 'हरित' दोनों अवधारणाओं को 'न्यायपूर्ण' की परिभाषा में समाहित करने की आवश्यकता है, तब 'न्यायपूर्ण' के आयाम में कौन से नए संघर्ष पाए जाने हैं? शहर के अनुभवों और संस्थानात्मक क्षमताओं की वैश्विक भिन्नताओं के साथ इस बात पर सरलता से कोई आम विद्वतापूर्ण समझदारी नहीं प्राप्त की जा सकती कि किसी शहर में न्याय का क्या अर्थ होगा या न्याय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और शहरों को और अधिक न्यायपूर्ण बनाने की चुनौती कभी इतनी बड़ी नहीं रही है (देखें, अध्याय 4).

वैश्विक दक्षिण के शहरों में न्यायपूर्ण शहरों की अवधारणा को भी प्रयुक्त होना है, चूँकि एक बेहतर विश्व के लिए अफ्रिका, एशिया और लैटिन अमेरिका के उभरते शहरों की शहरी स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। यह मुख्य रूप से सामाजिक पैमाने पर न्यायपूर्ण उपायों के बारे में है. न्यायपूर्ण शहर रोजाना की आधारभूत संरचनाओं में चाहे कि लैंगिकता, जातीयता, वर्ग या सांस्कृतिक पहचान जो भी हो तक सुगम पहुँच बनाने और शहरी जीवन में शामिल होने का मामला हे।

सुगम, हरित और न्यायपूर्ण शहर से टिकाऊ शहरों की ओर

इस पुस्तक ने टिकाऊ शहरों के तीन आयामों यथा सुगम, हरित और न्यायपूर्ण और उनके क्रमशः क्रमिक विकास, अवधारणात्मक आधार, वर्तमान आयामों और मुख्य मुद्दों पर विमर्श किया है। टिकाऊ शहरों की योजना बनाने हेतु एक स्पष्ट रणनीति को आकार देने के लिए अब हम इन तीनों आयामों को एकीकृत करते हैं।

पहले, इस एकीकरण को प्राप्त करने का कोई सार्वभौमिक तरीका नहीं है क्योंकि प्रत्येक सन्दर्भ विशिष्ट है और इस कारण प्रत्येक आयाम को दिया गया प्रासंगिक महत्व भिन्न होगा। हम प्रत्येक आयाम के प्रासंगिक ताकत या कमजोरी से प्रारम्भ करें।

दूसरे, उन बाधाओं और समस्याओं को समझना आवश्यक है जिनका सामना टिकाऊ शहरों का विकास कर सकता है। ये समस्याएँ तकनीकी, नौकरशाही सम्बंधित, संस्थानिक, कानूनी, वित्तीय और राजनीतिक हो सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ तक कि अच्छे ढंग से तैयार प्रगतिशील परिवर्तन परियोजनाएँ को भी बाधित किया जा सकता है, उनका रास्ता बदल दिया जा सकता है या उन्हें कमजोर कर दिया जा सकता है।

इसलिए यह आवश्यक कि तीनों आयामों को एक साथ एक ऐसी समग्र रूपरेखा के अंतर्गत रखा जाए जो अपरिहार्य चुनौतियों के बावजूद शोध, योजना और कार्यान्वयन को समेकित करती हो। किस प्रकार समेकित शहरी टिकाऊपन कार्यसूचियों को आगे ले जाया जाए इस हेतु यह पुस्तक शोधकर्ताओं, योजनाकारों और अन्य अधिकारियों साथ ही साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अन्य निर्णयकर्ताओं के लिए व्यावहारिक दिशा निर्देश पेश करती है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति हर संदर्भों संसाधनों तक पहुँच में न्याय की आवश्यकता को स्वीकार करता है हालाँकि न्याय और कार्यक्षमता के संतुलन के विषय में विभिन्न विचार हैं। इसलिए न्यायपूर्ण शहरों की अवधारणा सुगमता, हरीतिमा और न्याय के तीनों आयामों को एक साथ रखने का औचित्य सिद्ध करती है।

पहला व्यावहारिक कदम स्थानीय स्तर पर मुख्य हिस्सेदार समूहों के बीच समर्थन को लामबंद करना है और इस प्रकार विधान और अन्य नियमों की वर्तमान बाधाओं को दूर कर देना और वित्तीय संसाधन प्रदान करना है। अनुभव भी दिखलाते हैं कि मुख्य संगठनों के बीच सही संपर्कों का होना आवश्यक है। ऐसे लोगों को चिन्हित और उनका समर्थन करने की आवश्यकता है जो अपने अपने संस्थानों के अन्दर प्रभाव डाल सकतें हैं।

मतैक्य को ढूँढना और विश्वास विकसित करना बहुत ही आवश्यक पहलू है, जो एक जटिल, धीमा और पहले से अनुमान लगाने में कठिन प्रक्रिया हो सकती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि स्थानीय स्वीकार्यता के लिए स्थानीय विमर्श या शोध के वगैर सामान्य दिशा निर्देश या दुसरी जगहों की अनुशंसाओं और समाधानों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न नहीं किया जाए।

स्थानीय प्राधिकारों या अन्य संगठनों के पास पर्याप्त आतंरिक शोध क्षमता कदाचित ही होती है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ताओं को टीम में लाया जाए और इस प्रकार एक शोध संस्थान को क्षमता बढाने और परियोजना में आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य लाने के लिए हिस्सेदार के रूप में रखा जाए। इस प्रकार टीम के उद्देश्य में शोध और प्राप्त निष्कर्षों को व्यवहार में कार्यान्वित करने की योजना दोनों सम्मिलित है। इस प्रकार का समर्थन और साझेदारी से प्राप्त अधिकार एवं शोध निष्ठा अक्सर परियोजना को चलाने और अप्रत्याशित समस्याओं, जो बहुधा उठ खड़े होते हैं, से निबटने में बहुत सहायक है।

संबंधों को स्थापित और विकसित करना चुनौतीपूर्ण है। विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों के बीच गतिरोध को दूर करने और सहयोग का रास्ता निकालने में बहुत समय और प्रयास की आवश्यकता है। प्रत्येक मामले में संक्षिप्त प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है, आदर्शतः यदि पहले से चिन्हित हों तो इसका नेतृत्व अनुभवी परियोजना प्रबंधकों द्वारा हो लेकिन कुछ केवल प्रक्रिया के दौरान ही उभरेंगे और बाद में नियुक्त कर लिए जाएँगे। यह समय लेता है, यह जोखिम से मुक्त नहीं है एवं परिणाम अनिश्चित है। हालाँकि इस प्रक्रिया में कोई छोटा रास्ता नहीं है जो विश्वास निर्मित करने, सम्बन्ध बनाने और इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि स्थान हासिल हो सके जो शोध, प्रयोग और नवाचार के लिए साझेदार बन सके। दृ

साझा ज्ञान, अनुभव और दक्षता को परियोजना के अन्दर दूसरे शब्दों में, सामूहिक बौद्धिक संपत्ति के एक प्रकार के रूप में सुरक्षित रखना भी महत्वपूर्ण है। इनका निजीकरण नहीं होना चाहिए. हालाँकि इसमें उचित निजी क्षेत्र के साझेदारों को छोड़ नहीं देना चाहिए क्योंकि सामान्य बौद्धिक संपत्ति अधिकार को रखने की जरुरत को एक औपचारिक साझेदारी के समझौते का हिस्सा बनाकर संबोधित किया जा सकता है।

न्यायपूर्ण शहरों के पास हार्ड और सॉफ्ट दोनों आधारभूत संरचनाएँ अवश्य होनी चाहिए जो शहरी क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती हों और टिकाऊ गतिविधियों को मुमकिन करती हों। निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता की भी कसौटी अवश्य होनी चाहिए। अधिक बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता, और कुछ अपेक्षाकृत ऐसे छोटे हस्तक्षेपों के. जो किसी विशेष कमी को दूर करते हों, असामान्य रूप से बड़े प्रत्यक्ष और परोक्ष परिणाम (मल्टीप्लायर इफेक्ट्स – डनसजचसपमत मंमिबजे) हो सकते हैं।

प्रभावकारी रूप से भूमि का उपयोग होना भी बहुत महत्वपूर्ण है. सामान्य रूप से इस कार्य का प्रबंध एक या उससे अधिक स्तरों पर सरकारी संस्थानों द्वारा किया जाता है.। यह केवल हरीतिमायुक्त स्थलों पर निर्माण के बारे में नहीं है। यह हरीतिमाविहीन स्थलों पर भी निर्माण के विषय में है जिससे कि 'मृतप्राय', सामाजिक रूप से अलगावकारी और खतरनाक स्थानों की उपस्थिति को टाला जा सके। परम्परागत भूमि कानूनों से काम नहीं चलता। हालाँकि, नए समाधानों को सामान्यतः व्यापक समर्थन और स्वीकृति मिलती है उदाहरण के तौर पर कार्यान्वयन प्रक्रिया में जन–समर्थन के साथ अंतर्विषयक शोध पर आधारित समाधान. का लागू करना। प्रभावकारी भूमि–उपयोग लोगों के घरों, कार्यस्थलों और वाणिज्यिक एवं सामाजिक सुविधाओं के बीच की दूरी को कम कर देता है जो बदले में यात्राओं, यात्रा की दूरी और यात्रा के समय को कम कर देगा और इस प्रकार निजी मोटर वाहन स्वामित्व से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की ओर मुड़ने को बढ़ावा देगा.

विभिन्न तरीकों से व्यवहार–परिवर्तन को बढाने के लिए, जो टिकाऊपन को बढ़ावा देते हों, कर राजस्व का उपयोग किया जा सकता है। मोटर यातायात को कम करने के लिए बेहतर सार्वजनिक परिवहन के अतिरिक्त उदाहरण के तौर पर यह संभव है कि निर्धन और हाशिए पर के सामाजिक समूहों को प्राथमिकता दी जाए, संपत्ति दरों में अंतर किया जाए, अपनी–अपनी संपत्तियों में ऊर्जा को बचाने की गतिविधियों को चलाने के लिए निजी व्यक्तियों और कम्पनियों को प्रोत्साहित किया जाए जो सम्पूर्ण हरित आधारभूत संरचना, पानी और कचरे, इत्यादि के पुनरावर्तन में सहयोग करती हों।

इन सारे मुद्दों की व्यवस्था करने के लिए स्वैछिक कार्य और नियमों के बीच एक अच्छा स्थानीय संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। टिकाऊपन में परिवर्तन के विभिन्न चरणों में समय के साथ यह संतुलन बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर, सामाजिक और व्यवहार संबंधी परिवर्तन में कोई नियम प्रभावकारी रूप से तेजी ला सकता है, लेकिन एक बार जब बदलाव आ गया तो वह नियम उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। स्थानीय प्राधिकारों और नागरिक समाज का सक्रिय जुड़ाव भी, उदाहरण के तौर पर अंतर्विषयक साझेदारियों, स्वैच्छिक समूहों, गैर सरकारी संगठनों और विशेष तौर पर सामाजिक मीडिया के माध्यम से, आवश्यक है।

कभी–कभी किन्हीं आवश्यक कानूनों को, कम–से–कम एक अपेक्षाकृत अल्पावधि में, लागू करवाना कठिन हो जाता है। ऐसे मामलों में वर्तमान के अनुपयुक्त नियमों के लागू किए रहने को निष्क्रिय कर देना एक महत्वपूर्ण काम हो सकता है। एक सामान्य उदाहरण यह है कि ऐसे लोगों को, जिन्होंने खुले स्थानों पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए झुग्गी–झोंपड़ियाँ बना ली हों, उजाड़ नहीं देना बल्कि यदि यह आवश्यक नियोजित विकास में बाधा न डालता हो तो उनकी अवधि को नियमानुकूल कर उन्हें बुनियादी आधारभूत संरचना प्रदान कर देना। इसी को शहरी इलाकों के खुले स्थानों पर खेती किए जाने के सिलसिले में भी लागू किया जा सकता है. भले ही तकनीकी रूप से यह वर्जित हो। यह निर्धनतम निवासियों की भोजन सुरक्षा में सहायता करता है और शहरी हरितकरण में योगदान देता है।

अंततः, 2016 से सारे शहरों और स्थानीय प्राधिकारों को शामिल करनेवाली एक नई वैश्विक प्रवृत्ति के तौरपरं शहरों में उपयुक्त टिकाऊ निवेशों और नवाचारों को प्रेरित करने की महान संभावनाएँ हैं। यह 2016 से 2030 तक चलने वाले 17 टिकाऊ विकास उद्देश्यों (क्ळे) के समूह के अंतर्गत एक रूप से शहरी उद्देश्य का प्रवेश है। ;क्ळेद्ध पूरी दुनिया के सभी देशों पर प्रयुक्त होता है जो टिकाउपन की चुनौती वैश्विक स्तर पर अविभाज्य प्रकृति को दर्शाता है। सारे शहरों को समावेशी, सुरक्षित, टिकाऊ और लचीलापन की क्षमता वाला बनाने के लिए गोल 11 ;ळवंस 11 द्ध सात लक्ष्यों और तीन अनुपूरक लक्ष्यों कुल मिलाकर 17 सूचकांकों से पूरित है।

सारे स्थानीय प्राधिकारों के लिए वार्षिक प्रतिवेदन देना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि वर्तमान में सारे प्रासंगिक आँकड़े इकट्ठा नहीं किए हुए हैं या आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए लक्षित समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र (यू एन) के द्वारा प्रबोधन और मूल्यांकन होगा। इस प्रकार यह टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देने हेतु राजनीतिक नेताओं और स्थानीय प्राधिकार अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए लक्ष्यों और सूचकांकों के इस्तेमाल का एक अनूठा अवसर पेश करता है।

समर्थन और तंत्रजाल (नेटवर्किंग) के बाहरी स्रोत

समर्थन और नवाचारी पद्धतियों के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न बाहरी (नेटवर्क्स) मौजूद हैं। देशों के अपने अन्दर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सरकारें एवं शोध संस्थान प्रभावकारी बहुस्तरीय संचालन में लग सकते हैं। कुछ ऐसे सम्बन्ध जटिल या यहाँ तक कि विरोधी भी हो सकते है, उदाहरण के तौर पर यदि शक्तियाँ और उत्तरदायित्व अस्पष्ट हैं या विरोधपूर्ण कार्यसूचियों वाले राजनीतिक दल विभिन्न संस्थानों को नियंत्रित करते हों।

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और नेटवर्क भी विभिन्न प्रकार की सलाह, व्यावहारिक समर्थन और सीखने के संसाधन पेश करते हैं, उदाहरण के तौर पर :–

- टिकाऊपन के लिए स्थानीय सरकारें (आई सी एल इ आई – ICLEI)

- संयुक्त शहर और स्थानीय सरकारें (यू सी एल ज– UCLs)
- अग्रणी शहरों का सी 40 नेटवर्क (C40)
- स्मार्ट सिटीज काउन्सिल
- लन्दन में स्थित इंटरनेशनल ईश्टीच्यूट ऑफ इनवायरमेंट एण्ड डेवलपमेन्ट (IIED)
- यू एन की यू एन–हैबिटेंट (UN-HAVITAT) और यू एन इ पी (UNEP) एजेंसियाँ (जो नियमित प्रतिवेदन पेश करती हैं और जिनके पास शहरों की अलग–अलग श्रेणियों के लिए प्रासंगिक विशेष कार्यक्रम भी हैं।)

अंतिम निष्कर्ष

इस पुस्तक में एक समान सन्दर्भ बिन्दु यह है कि 20 वीं सदी के आगमन से ही यूटोपियन विचारधारा ने शहरी योजना को प्रभावित किया है। पूर्व की बहुत सारी यूटोपियन विचारधाराओं का मूल अराजकतावादी विचार में था। कार्यान्वयन एक दूसरी बात है। यह वास्तविकता की अपनी सारी जटिलताओं और विरोधाभासों के साथ हस्तक्षेप करने की प्रवृति है।

कार्यान्वयन की अनिवार्यता हर जगह अत्यंत महत्वपूर्ण है. खासकर वैश्विक दक्षिण में जहाँ शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और कल के शहर, आज जिनमें से कई पहले से ही निर्माणाधीन हैं, वैश्विक उत्तर के गैर–टिकाऊ शहरीकरण की नकल कर रहे हैं। वैश्विक दक्षिण में नए टिकाऊ विचारों के कुछ उदाहरण हैं जो देशी सांस्कृतिक और वास्तुशिल्पीय रूप रेखाओं को सर्वोत्तम 'अन्तर्राष्ट्रीय' औद्योगिक रूपरेखा. सामग्रियों और जीवन शैलियों के साथ मेल स्थापित करते हैं।

इस पुस्तक ने शहरों में विकसित होते हुए टिकाऊपन की कई समस्याओं और सीमाओं को उठाया है. हम प्रस्तावित करते हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता टिकाऊ शहरों के लिए एक समेकित पद्धति प्रयुक्त करने का है जिससे कि शहर आवश्यक रूप से सुगम, हरित और न्यायपूर्ण हो सकें।

इतना कहने के बाद ऐसी वैचारिकताओं और आकांक्षाओं में किसी स्थायित्व या अंतिम स्थिति के भाव से परहेज करना आवश्यक है। देशकाल के सन्दर्भ में स्थानीय रूप से प्रासंगिक रहने के लिए उन्हें आवश्यक रूप से लगातार क्रमिक रूप से विकसित होना चाहिए। शहरों को बेहतर स्थान बनाने और शहरी योजना में यूटोपियन विचार के प्रवक्ता जॉन फ्रीडमैन ने संयुक्त योजना व्यवहार पर अपने महत्वपूर्ण लेख को इस प्रकार निष्कर्षित किया है।

> *"शहर की मेरी छवि अपूर्ण रह गई , और मैं समझता हूँ यह ठीक ही है क्योंकि किसी के भी पास एक अच्छे शहर के लिए अंतिम कथन नहीं होना चाहिए. यूटोपियन विचार एक निरन्तर, समयबद्ध विमर्श है जिसका उद्देश्य हमारे प्रयासों को सामने रखना है. यह इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इससे कम भी नहीं."।*